कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

श्रावण–भाद्रपद 2082, अगस्त 2025

स्वदेशी पत्रिका और स्वदेशी परिवार की ओर से

स्वदेशी के सभी पाठकों, लेखकों
तथा स्वदेशी में योगदानकर्त्ता को

79वें

स्वतंत्रता दिवस

की

हार्दिक शुभकामनाएं

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–33, अंक–8
श्रावण–भाद्रपद 2082 अगस्त 2025

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

स्वदेशी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को समर्पित प्रधानमंत्री का भाषण

स्वदेशी उत्पाद यानी दाम कम, दम ज्यादा

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

09 मुद्दा
स्वदेशी स्वावलंबन ने निकाल दी ट्रंप के शुल्क डिप्लोमेसी की हवा
...... *अनिल तिवारी*

11 ग्रामीण भारत
साल पत्तों पर टिका है जंगल महल के आदिवासियों का आर्थिक जीवन
...... *डॉ. धनपत राम अग्रवाल*

14 दृष्टिकोण
असत्य एवं अविवेक पर आधारित ट्रंप की भ्रामक टैरिफ नीति
...... *विनोद जौहरी*

16 बहस
भारत–अमेरिका टैरिफ़ युद्ध का द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव
...... *दुलीचंद कालीरमन*

18 समीक्षा
भारत ने नहीं झुकाया सिर, ट्रंप की धमकी को दिया आंकड़ों से करारा जवाब
...... *अजय कुमार*

20 आर्थिकी
ट्रंप के टैरिफ टेरर से देश को उबारेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
...... *डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र*

22 तकनीकी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से पर्यावरण को लाभ कम, जोखिम ज्यादा
...... *स्वदेशी संवाद*

24 भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन में है वैश्विक समस्याओं का हल
...... *प्रहलाद सबनानी*

26 शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच वर्ष : नीति से अभ्यास तक
...... *विजय गर्ग*

28 आजकल
षड्यंत्र था भगवा आतंक का जुमला
...... *संध्या जैन*

30 विमर्श
कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है पीओके
...... *देवेश खण्डेलवाल*

32 अंतर्राष्ट्रीय
भारत–मॉरीशस संबंध को मज़बूत करती भोजपुरी
...... *सतेन्द्र त्रिपाठी*

34 वेदना
मातृभूमि के विभाजन की वेदना
...... *हेमेंद्र क्षीरसागर*

पाठकनामा

ट्रंप शुल्क, स्वदेशी सुरक्षा अभियान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा

अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने – जो भारत के रूसी तेल आयात जारी रखने से जुड़ा है – के बीच 86.5 अरब डॉलर के निर्यात, विशेषकर वस्त्र और रत्न जैसे श्रम–प्रधान क्षेत्रों, पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इससे रोजगार और आर्थिक विकास को खतरा है, जो एक मजबूत घरेलू रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रवादी आर्थिक संगठन 'स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम)' ने इसका तीखा जवाब "स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान" के रूप में दिया है। जून 2025 में शुरू हुआ यह अभियान, व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के व्यापक समर्थन के साथ, नागरिकों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील करता है।

एसजेएम का संदेश आर्थिक देशभक्ति को जमीनी प्रतीकों से जोड़ता है – किसानों, लघु उद्योगों और स्थानीय श्रमिकों को राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ के रूप में प्रस्तुत करता है। अभियान का जोर वैश्विक बाजारों पर निर्भरता कम करने और ऐसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर है जो भारत के किसानों और छोटे कारोबारों की रक्षा करें। रैलियों, सांकेतिक विरोधों और लक्षित जन–अपीलों के माध्यम से, यह आंदोलन आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की कोशिश करता है।

भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा हैः अल्पकालिक लाभ के लिए बाहरी दबाव के आगे झुकना, या दीर्घकालिक आर्थिक संप्रभुता के लिए कुछ समय के लिए कठिनाई सहना। स्वदेशी आंदोलन के लिए रास्ता स्पष्ट है – सामूहिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से आर्थिक मजबूती ही वैश्विक अनिश्चितताओं का स्थायी समाधान है।

विजित कुमार (स्वदेशी कार्यकर्ता), दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

भारत संरचनात्मक, नियामक, नीतिगत और प्रक्रियागत सुधारों के लिए प्रतिबद्धता के साथ एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहा है जहाँ शासन जनता के लिए काम करे।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

भारत की मूक तकनीकी क्रांति इस बात से परिलक्षित होती है कि अब लगभग 50 प्रतिशत भारतीय स्टार्ट–अप टियर–II और टियर–III शहरों से हैं, जिनमें से कई का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं... भारत का लक्ष्य सरकार–उद्योग तालमेल और स्वदेशी डेटा भंडार के माध्यम से वैश्विक तकनीकी नेतृत्व हासिल करना है।

जितेन्द्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत

वर्तमान समय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने तथा 2047 तक समृद्ध भारत के विजन को पूरा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षामंत्री, भारत

जीएसटी दरों में कमी और सरलीकरण केवल एक राजकोषीय कदम नहीं है, बल्कि एक स्वदेशी–उन्मुख सुधार है। यह घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, एमएसएमई को सशक्त बनाएगा, व्यापारियों और कारीगरों का समर्थन करेगा और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगा।

डॉ. अश्वनी महाजन, अ.भा.सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

भारत को स्वदेशी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चीन पर निर्भरता नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वदेशी को अपनाने का समय आ गया है। जो "मेक इन इंडिया" से शुरू हुआ, आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में विकसित हुआ, अब स्वदेशी के गहन और समग्र विचार की ओर बढ़ रहा है। यह केवल एक नारा नहीं है। यह एक सभ्यतागत अनिवार्यता है। यह सही है कि भारत चीन की उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। बीजिंग के साथ हमारा व्यापार घाटा हर साल 100 अरब डॉलर को पार कर जाता है। वर्तमान में, हमारे दो–तिहाई से ज़्यादा सौर मॉड्यूल, हमारी 70 प्रतिशत से ज़्यादा दवा सामग्री और अरबों डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स सीमा पार से आते हैं। ये सिर्फ़ संख्याएँ नहीं हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं। चीनी बंदरगाहों से आने वाला हर कंटेनर जहाज चीन पर हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। इसी संदर्भ में, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा को देखा जाना चाहिए। उनकी वहाँ उपस्थिति कोई रियायत नहीं; एक बयान है। भारत बातचीत करेगा, लेकिन स्पष्टता और विश्वास की स्थिति से। बातचीत का मतलब निर्भरता नहीं है। बातचीत का मतलब राष्ट्रीय हितों को कमज़ोर करना नहीं है। संदेश सीधा है, भारत जहाँ तक संभव हो, सहयोग चाहता है, लेकिन अपनी आर्थिक संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा।

हाल के अध्ययन, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझ परिषद (सीआइयू) द्वारा तैयार भारत के भू–आर्थिक ढाँचे में चीन अध्ययन के लिए रणनीतिक अनिवार्यता भी शामिल है, इस खतरे को रेखांकित करते हैं। ये अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे चीन का राज्य–प्रधान मॉडल – औद्योगिक अति–क्षमता, डंपिंग, सब्सिडी और वित्तीय इंजीनियरिंग – बाजारों को विकृत करता है और भारत के विनिर्माण आधार के लिए खतरा पैदा करता है। ये अध्ययन फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा में चीनी इनपुट पर हमारी खतरनाक निर्भरता की ओर भी इशारा करते हैं, और चेतावनी देते हैं कि संकट के समय ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं तक पहुँच को आसानी से हथियार बनाया जा सकता है। ये जानकारियाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट करती हैंः भारत प्रतिक्रियात्मक रुख नहीं अपना सकता; उसे स्वदेशी पर आधारित एक सक्रिय सिद्धांत अपनाना होगा।

चीन के दृष्टिकोण के विपरीत, स्वदेशी साम्राज्यवादी नहीं है। यह ऋण या जबरदस्ती के माध्यम से दूसरों पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। हमारा स्वदेशी वसुधैव कुटुम्बकम – दुनिया एक परिवार है – के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा दृष्टिकोण देश में आत्मनिर्भरता और विदेश में निष्पक्ष, सहयोगात्मक साझेदारी का है। यह भारत में न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करने के बारे में है, जो लचीलेपन और सम्मान को मजबूत करता है। वैश्विक स्तर पर, स्थिति बदल रही है। टैरिफ का हथियारीकरण – जो ट्रम्प की पहली पारी में स्पष्ट हुआ और अब वैश्विक व्यापार का एक अभिन्न अंग बन गया है – ने सरकारों और व्यवसायों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में, कंपनियाँ चीन के विकल्प तलाश रही हैं। जहाँ कई लोग इसे "चीन+1" कहते हैं, वहीं भारत को एक बड़े विचार को आगे बढ़ाना होगाः भारत+अनेक। भारत के पास विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र बनने के लिए पर्याप्त पैमाना, प्रतिभा और सभ्यतागत लोकाचार है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, हमें घरेलू क्षमताओं को और मज़बूत करना होगा। सरकार ने पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं – उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, और व्यापार धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों में संशोधन। ये उपाय, आसियान मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के भीतर भारत की पुनर्वार्ता और यूरोपीय संघ के साथ नए जुड़ाव के साथ, व्यापार नीति को राष्ट्रीय हित के अनुरूप बनाने की इच्छा को दर्शाते हैं। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

सीआईईयू अध्ययन सही ही सिफ़ारिश करता है कि भारत को अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश को दोगुना करके सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करना चाहिए – यह एक आवश्यक कदम है यदि हमें सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और अगली पीढ़ी की तकनीकों में नवाचार की खाई को पाटना है। यह सरकार के भीतर एक समर्पित चीन आर्थिक जोखिम निगरानी इकाई – जो जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने, चीनी प्रथाओं पर नज़र रखने और सक्रिय नीति निर्धारण को सूचित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र – की भी माँग करता है। दोनों ही ज़रूरी और आवश्यक हैं। साथ ही, स्वदेशी सिद्धांत–आधारित साझेदारी का आह्वान करता है। चाहे क्वाड, आसियान, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के माध्यम से, भारत को एक वास्तविक बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करना चाहिए। इसी तरह भारत "+1" की परिधि से "अनेक" के केंद्र की ओर बढ़ सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा कर रहे हैं, तो वे भारत के वार्ता संबंधी दायित्व से कहीं अधिक लेकर गए। वे भारत का संदेश लेकर गएः हमारा स्वदेशी सीमित नहीं है, यह व्यापक है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करता है, हमारे लोगों को सशक्त बनाता है, और एक अधिक न्यायसंगत विश्व व्यवस्था में योगदान देता है। ऐसे दौर में जब व्यापार हथियार बन गया है और आपूर्ति श्रृंखलाएँ युद्धक्षेत्र बन गई हैं, भारत का रुख़ दृढ़ होना चाहिए – हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमेशा अपनी शर्तों पर। दुनिया को दूसरे चीन की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को भारत की ज़रूरत है – एक ऐसे भारत की जो स्वदेशी में निहित हो और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के मार्ग पर चलता हो। ❑

स्वदेशी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को समर्पित प्रधानमंत्री का भाषण

स्वदेशी उत्पाद यानी दाम कम, दम ज्यादा

स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल क़िले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए स्वदेशी और सुरक्षा के अपने संकल्प को पुनः उद्घोषित कर, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने रोडमैप को देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मात्र 13 दिन पहले, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपने भाषण में स्वदेशी हेतु ज़ोरदार अपील करते हुए कहा था, ''यदि भारत को अपने हितों की सुरक्षा करनी है तो हर दल, हर नेता और हर नागरिक को स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा''। उन्होंने व्यापारियों और दुकानदारों से तो यह कहा कि इस स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री ही देश की सच्ची सेवा होगी, देशवासियों से भी उन्होंने अपील की कि हम भारतीय उसी सामान को ख़रीदें जिसमें देश के लोगों का पसीना बहा हो।

वर्तमान संदर्भ में, जब अमरीका समेत अन्य देश हमारे देश की स्वतंत्र आर्थिक और विदेश नीति और बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताक़त पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का यह आह्वान, एक विशेष महत्व रखता है। ध्यातव्य है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (कुल 50 प्रतिशत) थोपने और उसके ऊपर और जुर्माना भी ठोकने की घोषणा यह कह कर की है कि भारत रूस से तेल ख़रीद रहा है। ट्रंप ने यह कहा था कि भारत रूस से तेल ख़रीद कर रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध में मदद कर रहा है। हालाँकि भारत ने यह साफ़ कर दिया था कि अमेरिका इस संबंध में दोहरे मापदंड अपना रहा है क्योंकि वो स्वयं अभी भी अपनी ज़रूरत के लिए रूस से व्यापारिक सम्बन्ध लगातार बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के भाषण में अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वदेशी के महत्व को रेखांकित किया था। समझना होगा कि 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का यह भाषण कोई भावात्मक

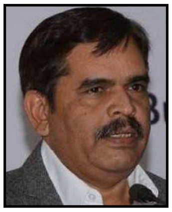

स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल क़िले से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए स्वदेशी और सुरक्षा के अपने संकल्प को पुनः उद्घोषित कर, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने रोडमैप को और देश के सामने प्रस्तुत किया।

– डॉ. अश्वनी महाजन

अपील मात्र नहीं है बल्कि उनकी सरकार का भारत को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु नीतियों की एक स्पष्ट दिशा का भी उद्घोष है।

हालाँकि 2014 में सत्ता के सूत्र संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने हेतु 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'कौशल विकास', 'उद्यमिता विकास' आदि को बार–बार दोहराते रहे हैं, लेकिन उसमें स्वदेशी के प्रति उनका इतना स्पष्ट आग्रह कभी नहीं रहा। देश को सशक्त बनाने में देश के युवाओं, वैज्ञानिकों महिलाओं और उद्यमियों की भूमिका के बारे में उन्होंने सदैव विश्वास व्यक्त भी किया और उसके सुखद परिणाम भी देखने को मिले। लेकिन कोविड के दौरान स्वदेशी की ताक़त का यह एहसास देश को तब हुआ जब पूरी दुनिया कोविड के सामने घुटने टेक चुकी थी। अपने आपको विकसित कहने वाले देश भारत जैसे विकासशील देशों को मदद देना तो दूर स्वयं की रक्षा करने में भी खुद को आश्वस्त नहीं मान रहे थे। ऐसे में भारत के समाज ने न केवल अपने आस–पास के परिवेश की सेवा और सुरक्षा की बल्कि भारत ने स्वयं के लिए वैक्सीन बनाकर समस्त जनसंख्या को सुरक्षित ही नहीं किया बल्कि दवा और स्वास्थ्य उपकरण बनाकर दुनिया को भी चकित कर दिया था, जिसके चलते भारत में कोविड का प्रभाव शेष दुनिया के मुक़ाबले बहुत की कम रहा।

स्वदेशी

प्रधानमंत्री, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए आज स्वदेशी के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के संकल्प को दोहराते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए उर्वरक तो बनाएँगे ही अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन भी बनाएंगे। समय आ रहा है कि हम वैश्विक बाज़ारों में अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ आगे बढ़ें। आज अनिश्चित वैश्विक माहौल में यह और भी ज़रूरी हो गया है। उन्होंने अपने ही अंदाज़ में इस बात को रेखांकित करते हुए कि ''भारत में उत्पादन सस्ते में तैयार होता है, हमें इस मंत्र पर काम करना होगा कि 'दाम कम और दम ज़्यादा'।'' प्रधानमंत्री का यह उद्घोष अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ताओं में आए गतिरोध और अमरीकी प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रतिकूल रूख के संदर्भ में एक विशेष महत्व रखता है। जहाँ भूमंडलीकरण के समर्थक, देशों के बीच, आपसी निर्भरता का तर्क देते रहे हैं, प्रधानमंत्री का यह कहना कि दूसरे देशों पर निर्भरता ख़तरनाक है और हमें अपने हितों के संरक्षण हेतु आत्मनिर्भर होना है, सीधे तौर पर भूमंडलीकरण के विचार को सिरे से ख़ारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के चलते भारत आत्मनिर्भर व्यापार और ऊर्जा स्वातंत्र्य की तरफ़ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अभी भी कई देशों पर निर्भर हैं, लेकिन एक सच्चे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करनी होगी। पिछले वर्षों में हमारी सौर उर्जा क्षमता 20 गुना बढ़ गई है। वर्तमान में 10 नए परमाणु रिएक्टर चालू है, और जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तब तक हमारा लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम सेमी कण्डक्टर की पहली खेप तैयार करने में सफल हो जाएंगे। अमेरिका द्वारा भारत के डेयरी और

स्वदेशी भारत की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रतीक होगा और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल दूसरों को कमज़ोर करने के लिए भी किया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी जागरण मंच इस प्रकार का आग्रह वर्षों से करता रहा है।

कृषि बाज़ार तक पहुँच की माँग पर ज़ोर देने के बीच, मोदी ने कहा कि वह भारत के किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग में कार्यरत लोगों के हितों की रक्षा के लिए "दीवार" की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये का है।

प्रधानमंत्री ने सभी छोटे और बड़े दुकानदारों से आग्रह किया कि उनके साइनबोर्ड पर यह लिखा होना चाहिए कि वे स्वदेशी सामान बेचते हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी भारत की कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रतीक होगा और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल दूसरों को कमज़ोर करने के लिए भी किया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी जागरण मंच इस प्रकार का आग्रह वर्षों से करता रहा है।

सुरक्षा

हाल ही में जब पाकिस्तान ने पहलगाम में अपनी कायरतापूर्ण हरकत से 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी तो पाकिस्तान के आतंकवादियों और उसकी सैन्य क्षमता को नेस्तनाबूत करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी प्रतिरक्षा क्षमता का दुनिया भर में जो प्रदर्शन भारत ने कर दिखाया उससे

पाकिस्तान की प्रतिरक्षा प्रणाली तो ध्वस्त हुई ही, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों और चीन का दंभ भी तोड़ने में हम सफल हुए। अभी तक ये देश अपने आप को बड़ी सैन्य शक्ति मानने का दंभ भर रहे थे। हालाँकि अमेरिका और यूरोप जो अपने स्वार्थ के कारण रूस और यूक्रेन के युद्ध को हवा देते रहे हैं, मात्र चार दिनों के ऑपरेशन सिंदूर से ही विचलित हो गए, और विश्व शांति की दुहाई देते हुए, युद्ध विराम की अपील करने लगे। उसका कारण यह था कि इन देशों को अपनी सैन्य वस्तुओं का बाज़ार ख़तरे में पड़ता दिखाई देने लगा था। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि पिछले सालों में भारत के सैन्य वस्तु निर्यात 6 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये तक पहुँच चुके हैं। प्रतिरक्षा सामानों का हमारा उत्पादन अब बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है।

सुरक्षा के मोर्चे पर, प्रधानमंत्री ने अगली पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के सभी स्थलों, रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ–साथ अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और पूजा स्थलों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सरकार के 'मिशन सुदर्शन चक्र' को प्रेरित किया है, जो तकनीक का उपयोग करके न केवल दुश्मन के हमले को बेअसर करेगा, बल्कि कई गुना ज़्यादा ताकत से "जवाबी हमला" भी करेगा।

घुसपैठ

हालाँकि समय समय पर प्रधानमंत्री और सरकार घुसपैठ की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके समाधान की ओर अपनी प्रतिबद्धता दिखाती रही है और घुसपैठियों पर कार्यवाही भी करती रही है, लेकिन एक मिशन के तहत इस समस्या से निपटने का पहला उद्घोष प्रधानमंत्री के भाषण में मिला। उन्होंने यह कहा कि घुसपैठ हमारे देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन ला रही है, जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ख़तरा उत्पन्न करती है। उन्होंने कहा, "यह (घुसपैठ) हमारी एकता, अखंडता और प्रगति के लिए भी संकट पैदा करती है। यह सामाजिक तनाव के बीज बोती है। दुनिया का कोई भी देश खुद को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता, तो हम भारत को उनके हवाले कैसे कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि, ''मैं कहना चाहता हूँ कि हमने उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह मिशन इस गंभीर संकट से निपटेगा और एक निश्चित समय सीमा में हमारे देश पर मंडरा रहे संकट का समाधान करेगा। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं''।

कर का बोझ कम, रोजगार का वादा

हालाँकि प्रधानमंत्री के भाषण का अधिकांश भाग, स्वदेशी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उद्योग, कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को समर्पित था, लेकिन अपने लगभग 110 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने सामान्य जन को प्रत्यक्ष लाभ देने की प्रतिबद्धता को भी नहीं छोड़ा। लोगों के लिए 'डबल दिवाली' का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा करेगी, जिसका उद्देश्य आम लोगों पर कर का बोझ कम करना है, जिससे दैनिक जरूरतों की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

युवाओं के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को 15,000 रुपये की राशि देगी। उन्होंने कहा कि सरकार उन कंपनियों का समर्थन करेगी जो नए रोज़गार पैदा करने में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से 3.5 करोड़ युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं।

सरकार ने इससे पहले 2024–25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत युवाओं को एक साल के लिए 5,000 रुपये प्रति माह का लाभ मिलता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर अगली पीढ़ी के सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करेगी। ❑❑

स्वदेशी स्वावलंबन ने निकाल दी ट्रंप के शुल्क डिप्लोमेसी की हवा

घरेलू वृद्धि को सहारा देने के लिए अब नीतिगत समर्थन बढ़ाना जरूरी होगा। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी उद्योग–कारोबार को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करना जरूरी होगा।

–अनिल तिवारी

वित्तीय वर्ष 2025–26 के पहली तिमाही के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है। यह सुखद परिणाम ऐसे में आया है जब दुनिया भर के देशों में टैरिफ टेरर फैला रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय आर्थिकी को पानी पी–पीकर 'मृत अर्थव्यवस्था' की संज्ञा देते फिर रहे हैं। लेकिन भारत ने विश्व के पैमाने पर चल रही उथल–पुथल के बीच अपने स्वदेशी स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए तमाम विरोधी एजेंसियों के पूर्वानुमानों को धत्ता बताते हुए यह साबित कर दिया है कि भारतीय आर्थिकी की जड़ें किसी सिरफिरे के फूंक मारने से खत्म होने वाली नहीं है बल्कि इसकी जड़े काफी मजबूत है।

मालूम हो कि अमेरिका लंबे समय से अपनी शर्तों पर भारत के साथ व्यापार समझौता के लिए ताने–बाने बुनता रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन को समझौते को अंतिम परिणति तक ले जाने की उम्मीद थी, लेकिन भारत देश हित खासकर किसानों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करने की नीति पर अडिग है। अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत व्यापार शुल्क लगाया था। उसे उम्मीद थी की टैरिफ के डर से भारत झुक कर समझौता करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन भारत राष्ट्रीय हितों को आगे कर तनकर खड़ा रहा। फिर क्या था बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीद का ठीकरा फोड़ते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत का शुल्क थोप दिया। अब कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। इसे भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बढ़े शुल्क के कारण भारत का निर्यात कारोबार प्रभावित हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा हानि लाभ का गुणा–भाग के बीच केंद्र की सरकार ने शुल्क की चुनौती से निपटने के लिए सुनियोजित कदम उठाने शुरू कर दिए। निर्यातकों को वृद्धि प्रोत्साहन देने, प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत करने और घरेलू खपत बढ़ने के उपाय के साथ–साथ व्यापार के वैकल्पिक विदेशी बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। अभी–अभी जापान के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका की शुल्क नीति का शिकार जापान भी है इसलिए वह भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। जापान ने भारत में अगले एक दशक में 60000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। भारत ने दुनिया के 40 देशों के साथ व्यापारिक संवाद का अभियान शुरू कर अमेरिका को यह संकेत दे दिया है कि भारत राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए पचास फीसद शुल्क से भारत के चमड़ा, कपड़ा, रत्न, मशीनरी, आभूषण, प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ने की आशंका जानकारों ने व्यक्त की है। लेकिन लगे हाथों अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर प्रकाशित वैश्विक रपटों में कहा जा रहा है कि भारत की घरेलू खपत मजबूत है। ऐसे में भारत की विकास दर में किसी चिंताजनक गिरावट की आशंका नहीं है। हाल ही में

वैश्विक रेटिंग एजंसी 'एसएंडपी' ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर पचास फीसद ऊंचे शुल्क लगाने से उसकी आर्थिक तरक्की पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। भारत की 'सावरेन रेटिंग' का नजरिया आगे भी सकारात्मक बना रहेगा। चूंकि भारत एक निर्यात–उन्मुख अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसे में उसे फिलहाल शुल्क संबंधी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 'एसएंडपी' का मानना है कि भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2025–26 में 6.5 फीसद के ऊपर ही रहेगी। इसी तरह सात अगस्त को 'मार्गन स्टेनली रिसर्च' के एक विश्लेषण में भी भारत की घरेलू मांग मजबूत होने की बात कही गई है।

इस समय भारत की विकास दर को मजबूत आंतरिक घरेलू आधार मिला हुआ है। अब इसे लगातार आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत की विकास दर 6.4 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर से दोगुना को सकती है। इसी तरह रेटिंग एजंसी 'क्रिसिल' ने अपनी रपट में कहा है कि भारत में घरेलू खपत में सुधार, भरपूर खाद्यान्न उत्पादन, बेहतर मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, महंगाई में कमी, सस्ते कर्ज और अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक संकेतों के कारण इस वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत की विकास दर 6.5 फीसद के स्तर पर होगी।

हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई घटने से भी घरेलू बाजार में खपत को बढ़ावा मिल रहा है। खुदरा महंगाई घट कर आठ वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। सस्ते कर्ज से उद्योग–कारोबार में उत्साह है। कृषि क्षेत्र में रेकार्ड उत्पादन, मानसून की अच्छी प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर और मजबूत खरीफ बुवाई से सकारात्मक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, नवउद्यम, नवोन्मेष, तेजी से बढ़ता बाजार और सेवा क्षेत्र की ऊंचाइयां ऐसी शक्तियां हैं, जो दुनिया के देशों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

खुदरा महंगाई का अनुमान आरबीआइ ने घटाया है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अनुमान 3.7 फीसद से घटा कर 3.1 फीसद कर दिया है। जून 2025 में खुदरा महंगाई घट कर 2.1 फीसद पर आ गई। मई में खुदरा महंगाई दर 2.82 फीसद रही। इतना ही नहीं, जून में थोक महंगाई दर भी 20 महीने में पहली बार ऋणात्मक हुई। यह घट कर –0.13 फीसद रह गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेपो रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50 फीसद की कटौती का एलान किया। अब रेपो रेट छह फीसद से घट कर 5.5 फीसद हो गया है। इस वर्ष 2025 में फरवरी से अब तक लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी एक फीसद की बड़ी कटौती करते हुए इसे तीन फीसद पर ला दिया है।

निश्चित रूप से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को नया रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए समझौते अहम हैं। भारत को संयुक्त अरब और आस्ट्रेलिया के साथ समझौते से लाभ हुआ है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित एफटीए पर 24 जुलाई को हस्ताक्षर हुए। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में दस जुलाई को भारत में स्विटजरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी ने कहा कि भारत और चार सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौता अक्तूबर 2025 से लागू हो जाएगा। इन सबके साथ–साथ भारत–आसियान के बीच मौजूदा व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चर्चा जारी है। आसियान में ब्रुनोई, कांबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। पिछले सप्ताह भारत और जापान के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार समझौता हुआ है।

ऐसे में महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू वृद्धि को सहारा देने के लिए अब नीतिगत समर्थन बढ़ाना जरूरी होगा। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी उद्योग–कारोबार को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित करना जरूरी होगा। ❑❑

साल पत्तों पर टिका है जंगल महल के आदिवासियों का आर्थिक जीवन

जंगल महल पश्चिम बंगाल का एक पिछड़ा हुआ इलाक़ा है, जहाँ ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। उपजाऊ भूमि प्रायः नगण्य है। ज्यादातर लोग जंगलों पर आधारित कुछ विशेष पत्तों और कुछ विशेष प्रकार की घास पर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इनमें विशेष रूप से साल–पत्ता और सवाई घास पर आधारित जीवन है। लगभग 32 लाख लोग साल पत्ते पर और लगभग 12 लाख लोग सवाई घास पर आधारित जीविका चलाते हैं। यह अंचल झारग्राम जिले और पश्चिम मिदनापुर के तीन–चार ताल्लुकों में तथा थोड़ा सा हिस्सा बांकुड़ा और पुरुलिया जिले का है। पिछले 75 वर्षों की राजनैतिक स्वाधीनता के वावजूद यहाँ के निवासी घोर ग़रीबी और आर्थिक तंगी से त्रस्त हैं। कुछ लोग तो साल वन से सिर्फ़ पत्ते तोड़कर उन्हें तरह–तरह के बर्तन बनाने के लिये बेच देते हैं। इन पत्तों को तोड़कर मंडी तक पहुँचाने के काम में बहुत सी स्वयंसेविका समूह की महिलायें काम करती है, जिन्हें 0.70 पैसे से एक रुपये की क़ीमत प्रति प्लेट के आधार पर औसतन मिलते हैं। 6–7 पत्तों को धागे से सिलाई करके एक पत्तल तैयार की जाती है। इसके अलावा छोटी कटोरी और थाली के आकार के घरेलू बर्तन छोटे–छोटे घरेलू कुटीर शिल्प द्वारा निर्मित किये जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में महिलायें ही ज़्यादा काम करती हैं और औसतन 5000/– रुपये की मासिक आय उन्हें होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक तथा खादी ग्रामोद्योग, जो केंद्रीय और राज्य सरकार के युग्म प्रयास से संचालित होते हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण तथा कौशल विकास में भी मदद पहुंचाई जाती है। शुरुआती दिनों में साल पत्तों से बनी वस्तुओं पर जीएसटी देना पड़ता था, जिसे पत्ता श्रमिक संघ के लगातार प्रयासों के पश्चात जीएसटी हटा दिया गया है। परंतु यह जीविका का साधन अभी भी कई अन्य समस्याओं से जूझ रहा है,जिनमें थर्मोकोल द्वारा

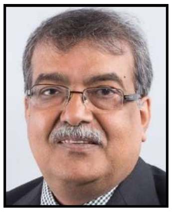

'सबका साथ और सबका विकास' तभी संभव हो सकेगा, जब हम पिछड़े इलाक़ों विशेषकर जंगल, पहाड़ तथा समुद्र के किनारे रहने वाले, जिनमें उत्तर बंगाल, सुंदरवन तथा जंगल महल के पिछड़े जिले शामिल हैं, जब इनका सर्वांगीण विकास किया जायेगा।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

निर्मित चाय– नाश्ते से संबंधित उत्पाद शामिल हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय तथा अन्य कई पर्यावरण अधिकारियों द्वारा रोक लगाये जाने तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कई बार ज्ञापन देने के वावजूद थर्मोकोल उत्पादों पर प्रभावी ढंग से रोक नहीं लग पाई है जो साल पत्ता व्यवसाय के विपणन व्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा है।

साल पत्ता तथा सवाई घास के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कुछ अनुसंधान केंद्र भी झारग्राम में बने हैं तथा इन उत्पादों के हस्तशिल्प संबंधी केन्द्रों में स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से उचित कौशल विकास की व्यवस्था की जा रही है, किंतु विपणन की व्यवस्था की कमी के वजह से श्रमिकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी की वजह से इस इलाके में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बहुत गंभीर रूप ले रही है। आर्थिक असमानता की एक वजह यह रही कि जंगल महल के इस अंचल में नक्सलवाद और सामाजिक असंतोष की झलक मिलती रहती है।

जंगल उत्पादों को जीवन और जीविका से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में चाय पत्ता, तंबाकू पत्ता, पान पत्ता, केंदु पत्ता और साल पत्ता का सामूहिक रूप से अर्थनीति में अवदान देखें तो पता चलेगा कि सिर्फ इन पाँच पत्तों पर 50 लाख से ज़्यादा लोगों की जीविका निर्भर है।

पुरुलिया जिले में लाख की खेती होती है, जो कुसुम और पलास के वृक्षों के रस से प्राप्त होता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित शेलक यानी लाख निर्यात निगम द्वारा इसके उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। हाल के समय में इस उद्योग के उत्पादन में काफ़ी कमी आ रही है।

इसी तरह बीड़ी बनाने के काम में आने वाले केंदू अथवा तेंदू पत्ते की भी खेती इस पूरे जंगल महल में होती है, जिससे लगभग 2 लाख लोगों की जीविका चलती है। हालांकि इससे प्राप्त प्रति व्यक्ति औसतन आय सिर्फ 4000–5000 रुपये मासिक के बराबर ही होती है, इसे बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है। एक बिनपुर नामक ताल्लुके, झारग्राम जिला का अध्ययन किया गया,जिसमें यह पाया गया कि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक वन अधिकार (आईएफआर/सीएफआर) वन विभाग अधिनियमों के अनुसार एक ग्राम सभा को साल पत्ता तोड़ने का और उनको मोड़कर पत्तल बनाने का अधिकार दिया जाता है और उसे नाबार्ड और खादी ग्रामोद्योग द्वारा मशीन उपलब्ध कराके संचालित किया जाता है, तो निम्न उत्पादकता मिल सकती है –

साल पत्ता तथा सवाई घास के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये कुछ अनुसंधान केंद्र भी झारग्राम में बने हैं तथा इन उत्पादों के हस्तशिल्प संबंधी केन्द्रों में स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से उचित कौशल विकास की व्यवस्था की जा रही है, किंतु विपणन की व्यवस्था की कमी के वजह से श्रमिकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

ग्रामसभाः (ग्राम का नाम), *ब्लॉकः* बिनपुर, झाड़ग्राम (जंगलमहल), *मुख्य एमएफआरः* साल पत्ता, केंदु पत्ता, महुआ फूल, बाँस (MFP- Minor Forest Produce)

स्थानीय प्रसंस्करण योजना

- साल पत्ता प्लेट यूनिट (ग्रामसभा द्वारा सामूहिक रूप से)
- 2 मशीनें (KVIC/NABARD सहायता से)
- प्रतिदिन 12,000 प्लेट उत्पादन (मई–जून)
- केंदु पत्ता
- बंडलिंग व ग्रेडिंग ग्रामसभा द्वारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत विपणन
- महुआ फूल
- भंडारण व सुखाना, SHG द्वारा पैकिंग व बिक्री
- बाँस
- ग्रामसभा ट्रांज़िट पास जारी कर छोटे उद्यम/कारीगरों को बिक्री

लेकिन पश्चिम बंगाल में सामुदायिक वनाधिकार की कार्यान्वयन–प्रगति वर्षों से कमजोर बताई जा रही है इससे ग्रामसभाओं को MFP, चराई, संरक्षण व बाज़ार प्रबंधन की वास्तविक शक्तियाँ नहीं मिल पातीं। इन क़ानूनों का उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों से वंचित नहीं बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा करना है ताकि उनके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के अनुकूल वन साधनों का उपयोग अपनी जीविका पालन के लिये सुचारू रूप से कर सकें। साल पत्ता और सवाई घास को टिम्बर कटाई कानून से अलग रखा गया है फिर भी जन जातियों की स्वायत्तता को बाधा पहुंचाई जाती है।

व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकार (IFR@CFR): वनाधिकार कानून, 2006 (FRA) का उद्देश्य अधिकार देना है– परंपरागत उपयोग की जमीन, चूल्हा–चेरा, चारा, ईंधन, छोटी लकड़ी, बाँस–झाड़ सहित लघु वनोत्पाद (MFP) पर स्वामित्व/उपज/बेचने का अधिकार। 2012 के संशोधित नियमों के बाद बाँस व अन्य MFP की ढुलाई के ट्रांज़िट परमिट ग्रामसभा/उसकी समिति जारी कर सकती है। आज समय की माँग है कि आदिवासियों के इन सभी अधिकारों की रक्षा हो और इसके लिये सरकारी अधिनियमों में लचीलेपन की आवश्यकता है। वन क्षेत्रों से आदिवासियों के पलायन को रोकने के लिये भी उनके अधिकारों के संरक्षण तथा उनके हितों के संवर्धन की आवश्यकता है।

"यदि ग्रामसभा को CFR का औपचारिक अधिकार व ट्रांज़िट पास जारी करने की शक्ति मिलती है, तो साल व केंदु पत्तों के मूल्य–संवर्धन से गाँव स्तर पर रू. 24 लाख वार्षिक आय संभव है। इससे आजीविका स्थिर होगी, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और स्थानीय स्वशासन मज़बूत होगा।"

जंगल महल में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और पर्यटन विकास के अवसर है। जंगल महल (झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया) क्षेत्र में घने साल के जंगल और पहाड़ी इलाक़े हैं। यहाँ बाघमुंडी हिल्स, अजोध्या हिल्स, बाघमुंडी अरण्य, मुकुटमणिपुर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं।

रोजगार के अवसर

जंगल महल में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और पर्यटन विकास के अवसर है। जंगल महल (झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया) क्षेत्र में घने साल के जंगल और पहाड़ी इलाक़े हैं। यहाँ बाघमुंडी हिल्स, अजोध्या हिल्स, बाघमुंडी अरण्य, मुकुटमणिपुर क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं।

यहां के पहाड़ी, जंगल, झरने (खैराबेरा, मरबेन, बांधोनी) को इको–फ्रेंडली टूरिज़्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है।

अजोध्या और झारग्राम बेल्ट में हाथी, हिरण, मोर आदि पर आधारित वाइल्ड लाइफ सफारी और बर्ड वॉचिंग सफारी तथा पुरुलिया, विष्णुपुर और आसपास में छऊ नृत्य पर आधारित सांस्कृतिक टूरिज़्म का बड़ा अवसर है।

लोक कला व हस्त शिल्प जैसे मुखौटे, मिट्टी की मूर्तियाँ, बाँस और लकड़ी की कारीगरी में भी संभावनाएं हैं।

विष्णुपुर (बांकुड़ा) का मदनमोहन मंदिर, श्यामराय मंदिर आदि विश्व प्रसिद्ध है। बलुचरी साड़ी और डोकरा शिल्प यहाँ की पहचान है। विष्णुपुर को UNESCO हेरिटेज सर्किट से जोड़कर विकसित किया जा सकता है।

सरकार की भूमिका

- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
- सड़क, रेल, हवाई (दुर्गापुर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी), और होम–स्टे टूरिज़्म।
- *स्मार्ट टूरिस्ट सर्किट* – "बिष्णुपुर–पुरुलिया–झारग्राम–मुकुटमणिपुर" के रूप में।
- मार्केटिंग व ब्रांडिंग
- "जंगल महल टूरिज़्म ब्रांड" को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना।
- ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर हस्त शिल्प व वस्त्र उत्पादों की बिक्री बढ़ाने हेतु ई–मार्केटप्लेस (ONDC) से जोड़ना।
- लघु उद्योग और सहकारी समितियाँ
- KVIC, NABARD और MSME योजनाओं के माध्यम से हस्त शिल्पकारों को क्रेडिट और डिज़ाइन ट्रेनिंग।
- शिल्प मेलों और अंतरराष्ट्रीय एक्सपो के जरिए सांस्कृतिक संरक्षण, छऊ नृत्य महोत्सव और टेरेकोटा महोत्सव जैसे उत्सवों का आयोजन, युवा पीढ़ी को लोक कला व हस्त शिल्प में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष केंद्र खोलना, महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से साल पत्ता प्लेट निर्माण, बुनाई और हस्त शिल्प के साथ स्थानीय युवाओं को गाइड, होम–स्टे प्रबंधक, टूर ऑपरेटर के रूप में रोजगार देना, प्रमुख है।

निष्कर्षः जंगल महल क्षेत्र पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प की दृष्टि से पूर्वी भारत का एक उभरता हुआ केंद्र बन सकता है।

'सबका साथ और सबका विकास' तभी संभव हो सकेगा, जब हम इन पिछड़े इलाक़ों विशेषकर जंगल, पहाड़ तथा समुद्र के किनारे रहने वाले, जिनमें उत्तर बंगाल, सुंदरवन तथा जंगल महल के पिछड़े जिले शामिल हैं, जब इनका सर्वांगीण विकास किया जायेगा। ❑❑

असत्य एवं अविवेक पर आधारित ट्रंप की भ्रामक टैरिफ नीति

वर्तमान में विश्व भर से अमेरिकी टैरिफ नीति पर तीखी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीति केवल उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा और अमेरिका फ़र्स्ट के उनके ध्येय के लिए समकक्षी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करना है। निश्चित रूप से भारत उनका लक्ष्य है। जिस दुराग्रह से उन्होने ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया है उससे तो कोई संदेह नहीं रह जाता कि उनकी भारत के प्रति टैरिफ नीति का दोनों देशों के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। वैश्विक परिपेक्ष्य में भी यही दृश्य परिलक्षित होता है। यह सही हैं कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल अभी भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता में हैं, जिसका परिणाम अभी समझना कठिन है। अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विभिन्न देशों के साथ भारी टैरिफ ड्यूटी लगाने के निर्णय से वैश्विक व्यापार में बढ़े स्तर पर भूकंप खड़ा कर दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीति का विरोध हो रहा है और इसके संवैधानिक औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लग गये हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए आठ दशक बीत गये हैं परंतु विश्व की महाशक्तियों को अभी यह समझ नहीं आया है कि उनके वर्चस्व के पराभव का समय आ चुका है। इनके वर्चस्व का सबसे बड़ा हथियार संयुक्त राष्ट्र संघ है और जिसका सबसे पहला शिकार भारत ही है जिसके संरक्षण और प्रभाव से भारत का विभाजन हुआ और आज तक न केवल भारत उसके परिणाम भुगत रहा है बल्कि विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान और वर्तमान बंगलादेश पूरी तरह बर्बाद हुए हैं जिनकी कुल बयालीस करोड़ जनता लगातार धार्मिक उन्माद, गृह युद्ध जैसी स्थिति, अशांति और आर्थिक कंगाली झेल रही है। विश्व की महाशक्तियों ने दुनिया को कितने ही युद्धों में धकेला है और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रखा है। इसके अलावा अफ्रीका में भुखमरी और विश्व में महामारियों के समय इन महाशक्तियों का असंवेदनशील चरित्र उजागर हुआ है जिसका सबसे नया उदाहरण कोरोना महामारी है। पिछले आठ दशकों में इन महाशक्तियों विशेष कर अमेरिका का सबसे अधिक हस्तक्षेप का क्षेत्र पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया है जहां युद्ध की ज्वाला और ज्वालामुखी धधकते रहते हैं। विश्व में इस विनाशलीला को विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर तमाशा देखती रहती हैं। विनाश की इस परिक्रमा में वैश्विक व्यापार तो बहुत छोटा सा पक्ष रह जाता है, उसमें भी अमेरिका और चीन की वर्चस्ववादी एवं संरक्षणवादी नीतियां और विश्व व्यापार संगठन की विवशता और उसके इन महाशक्तियों को समर्थन देना विकासशील देशों के प्रति दुराग्रह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी इन्हीं महाशक्तियों की कठपुतलियाँ हैं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान जैसे देशों को पुरस्कार के रूप में अनुदान देती हैं। यदि स्पष्टता से स्वीकार करें तो इन महाशक्तियों की समृद्धि दूसरे देशों के आर्थिक शोषण से है।

टैरिफ के चलते छंटनी की संभावनाओं के संदर्भ में अपने अंतिम कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर पच्चीस प्रतिशत टैरिफ और रूस से पैट्रोलियम खरीदने पर भारी जुर्माने के समाचार से अमेरिका के एक सुपर पावर होने योग्य व्यवहार को

भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्षों को सुधारने और भविष्य के मार्ग पर विचार करने की आवश्यकता है।

– **विनोद जौहरी**

नहीं दर्शाता है। भारत को अमेरिका से रक्षा और शोध, टैक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में व्यापार पर प्रभाव पड़ना तय है। इस बीच पाकिस्तान में कच्चे तेल के भंडार और उत्पादन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो नया विमर्श खड़ा किया है उसका लाभ सीपैक के कारण चीन को है, अमेरिका को तो किसी भी दृष्टि से लाभ की संभावना नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तानी तेल को लेकर भारत, तेल उत्पादक देशों और चीन पर एक साथ लक्ष्य साधने का जो प्रयास किया है, वह निष्फल है। अमेरिका ने यह देख और समझ लिया है कि भारत झुकने वाला देश नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। टैरिफ पर भारत की सधी हुई प्रतिक्रिया प्रशंसनीय है।

भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहकर उन्होंने देश का घोर अपमान किया है और यह भारत के आत्म सम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। हम अमेरिका के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मित्र रूस को नहीं छोड़ सकते। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को अपने रास्ते बदलने होंगे और यह प्रतिस्पर्धा दीर्घकालिक है। भारत ने प्रारम्भ से ही स्पष्ट कर दिया है कि हम अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में आने की अनुमति नहीं दे सकते और अपने किसानों को किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने देंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने छोटे और माध्यम औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे उद्योग व्यापार की आधे से अधिक भागीदारी एम एस एम ई क्षेत्र की है।

जिस रूस से पैट्रोलियम खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लिया है, उसी रूस से अमेरिका 5.2 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प को यह समझना होगा कि अमेरिका की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मेरुदंड विदेशों से विदेशी व्यापार, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रायल्टी, लाइसेंस, विदेशी नागरिकों के पर्यटन, विदेशी विद्यार्थियों की फीस, वीजा से आय पर निर्भर है। जिन एशियाई देशों से ट्रंप टैरिफ नीति के बल पर आक्रामकता दिखा रहे हैं, उन सभी देशों भारत, रूस, चीन, जापान और दक्षिण एशियाई देशों सहित एशियाई देशों की कुल जीडीपी 41 ट्रिलियन डॉलर है जो अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।

आंकड़ों की दृष्टि से भारत अमेरिकी व्यापार को देखें तो अमेरिका का भारत से आयात 87.3 बिलियन डॉलर है जो कुल अमेरिकी आयात 3.17 ट्रिलियन डालर का मात्र 2.75 प्रतिशत है। अमेरिका का भारत को निर्यात 41.4 बिलियन डॉलर है जो कुल अमेरिकी निर्यात 3.052 ट्रिलियन डॉलर का मात्र 1.34 प्रतिशत है।

अमेरिका का कुल व्यापार घाटा 1.1 ट्रिलियन डॉलर है जबकि भारत के साथ कुल व्यापार घाटा 45.7 बिलियन डॉलर के समतुल्य 4.1 प्रतिशत है। केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा अमेरिका को 87.3 बिलियन डॉलर के निर्यात और अमेरिका से भारत द्वारा 45 बिलियन डॉलर के आयात से इतर अमेरिका को यह भी समझना होगा कि भारतीय विद्यार्थियों से अमेरिका को 8 बिलियन डॉलर की आय होती है। अकेला कोका–कोला भारत में 290 मिलियन डॉलर का व्यापार करता है। अमेरिकी इंवेस्टमेंट कंपनियां भारत में 40 बिलियन डॉलर का व्यापार करती हैं। अकेले अमेज़न जैसी विशालकाय ई कामर्स कंपनी भारत में 13 बिलियन डॉलर का व्यापार करती है। इस प्रकार भारत के साथ अमेरिका का लाभ का व्यापार है। भारत के साथ अमेरिका ने अपमानजनक व्यवहार करके आपसी संबंधों में गहरी दरार डाली है जो उसके एशिया में राजनयिक एवं सामरिक प्रभाव को क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए अमेरिका – भारत व्यापार में व्यापार घाटा भारत के लिए है और अमेरिका के लिए सरप्लस है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर को भ्रमित किये हुए हैं।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी के मंत्र ही एकमात्र सफलता का सूत्र है। चीनी उत्पादों के अब भी घरेलू बाजार में बिकने का कारण यही है कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन के सामान बनाने वाले उपक्रम बहुत छोटे स्तर पर हैं जिनको माइक्रो स्तर की औद्योगिक इकाई समझ सकते हैं जिनका उत्पादन बहुत सीमित क्षेत्र में आपूर्ति होती है या रेहड़ी पटरी पर बिकने वाले उत्पाद होते हैं। बहुत सीमित पूंजी,पुराने और लोकल मशीन, परिवार तक सीमित रोजगार देने वाले उपक्रम कभी भी चीन के सस्ते और नये उत्पादों का सामना नहीं कर सकते। फर्नीचर के मामले में भी बहुत छोटे व्यापार हैं जो केवल अपने बाजार तक ही आपूर्ति करने में सक्षम हैं। यह तो सही है कि इसलिए बहुत आवश्यक है कि घरेलू आवश्यकता की वस्तुएं विशाल स्तर पर भी निर्मित हों जो संपूर्ण देश में आपूर्ति श्रृंखला को पोषित कर सकें और कीमतों में भी विदेशी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा दे सकें। इससे आगे भी सोचने की आवश्यकता है कि अब भारतीय मूल आधिक्य देशों में भी हमारे कारपोरेट हमारे स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन के लिए स्थानीय उद्योगपतियों के साथ साझीदारी में उद्योग स्थापित करें जिससे भारतीय उत्पादों का विदेशों में, विशेषकर भारतीय मूल के करोड़ों विदेशी नागरिक उपयोग करें। भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जाये। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्षों को सुधारने और भविष्य के मार्ग पर विचार करने की आवश्यकता है। ❑❑

भारत–अमेरिका टैरिफ़ युद्ध का द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

भारत–अमेरिका टैरिफ युद्ध ने अल्पावधि में व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा किया है। इस व्यवधान के समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ता, पारदर्शी नीति और संतुलित शुल्क प्रणाली आवश्यक है।

– दुलीचंद कालीरमन

भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े लोकतान्त्रिक देश और वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अतिरिक्त वैश्विक शक्ति–संतुलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक दुसरे के अहम् सांझेदार भी है। पिछले दो दशकों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं रणनीतिक संबंध तेज़ी से बढ़े हैं लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ़ (शुल्क) नीतियों ने व्यापारिक रिश्तों के साथ–साथ रणनीतिक संबंधों में भी खटास पैदा कर दी है।

हांलाकि टैरिफ़ युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यकाल में 2018 के बाद हो गई थी जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ाए थे और भारत ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। भारत को अमेरिका से टैरिफ़ के मामले में टकराहट का अंदेशा उसी समय हो गया था जब अमेरिकी प्रशासन ने "अमेरिका प्रथम" नीति के तहत अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात शुल्क बढ़ा दिए। भारत ने भी अमेरिकी बादाम, अखरोट, सेब, मोटरसाइकिल पाटर्स आदि पर अतिरिक्त शुल्क लगाए। 2019 में अमेरिका ने भारत को दिए गए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी.एस.पी.) लाभ समाप्त कर दिए, जिससे लगभग +5.6 बिलियन मूल्य के भारतीय निर्यात प्रभावित हुए। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली एक अमेरिकी व्यापार नीति है जो विकसित देश विकासशील देशों को कुछ उत्पादों पर शुल्क में छूट या कमी प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।

डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से भारत को "टैरिफ किंग" कहकर बदनाम कर रहे है। अमेरिकी सरकार के अनुसार, 2024 में भारत से व्यापार में उसे 45.8 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ लेकिन यह आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि अगर हम अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा भारत से कमाये जाने वाले राजस्व और अन्य मदों की आय को जोड़ दें तो यह आंकड़ा अमेरिका के पक्ष में जाता है। भारत से अमेरिका को मुख्यत फ़ार्मास्यूटिकल्स

(दवाइयाँ), वस्त्र और रेडीमेड कपड़े, हीरे–गहने, सॉफ़्टवेयर और सॉफ्टवेर सेवाएँ, औद्योगिक मशीनरी निर्यात की जाती है जबकि अमेरिका से भारत कच्चा तेल और एलएनजी, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, मशीनरी, मेडिकल उपकरण, कृषि उत्पाद (सोयाबीन, बादाम, आदि) आयात करता है। अमेरिका भारत पर कृषि और डेयरी क्षेत्र को अनुमति देने का दबाव बना रहा है जबकि भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

अमेरिका द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात का बहाना बनाकर भारत पर दबाव डालने के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। जबकि भारत ने रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदकर वैश्विक स्तर पर डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाया था, जिसकी वजह से वैश्विक तेल की कीमतें ज्यादा ऊपर नहीं जा पाईं थीं। यह भारत द्वारा लिए गया एक रणनीतिक कदम था। ट्रंप के अनुसार भारत का यह कदम न्यायापूर्ण नहीं था। हालांकि भारत ने साफ किया कि दूसरे देशों को नजरअंदाज करके केवल भारत पर निशाना साधना बेबुनियाद है। भारत का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के साथ यूरेनियम और पैलेडियम जैसे सामानों का व्यापार जारी रखे हुए हैं। जबकि भारत पर रूस से तेल आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर दण्डित करने का प्रयास हुआ हैं। ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और रूस के गहरे होते ऊर्जा संबंध अमेरिका के हिंद–प्रशांत रणनीति में उसकी भूमिका से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं।

दरअसल यह ट्रेड वॉर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। रूस के साथ

भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका उद्देश्य एक राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। भारत पर लगाया गया दंडात्मक शुल्क दोनों देशों के बीच पिछले दो दशकों की कड़ी मेहनत से बनाए गए विश्वास और सहयोग को खतरे में डाल रहे हैं।

भारत के रक्षा संबंध हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक स्तंभ हैं। इसके 60 प्रतिशत से अधिक सैन्य उपकरण रूस से आयात होते हैं। यह निर्भरता भारत के लिए रूस को एक महत्पूर्ण रणनीतिक साझेदार बनाती है। ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ को व्यापक रूप से "भू–राजनीतिक दबाव" की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत पर दीर्घकालिक सहयोगी रूस से संबंध जारी रखने या अमेरिका के साथ अपने संबंधों का चयन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। ताकि भारत को रूस से दूर करके रूस–यूक्रेन युद्ध का अपनी शर्तों पर युद्धविराम करवाया जा सके।

हालाँकि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद ने व्यापार में चुनौतियाँ पैदा कीं, लेकिन रक्षा और तकनीकी सहयोग पर इनका ज्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ा। भारत और अमेरिका दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क हैं, इसलिए रणनीतिक साझेदारी अभी भी बनी हुई है। यदि यह टैरिफ विवाद लंबे समय तक चलता रहा तो यह निवेश प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग, और स्टार्टअप–टेक सेक्टर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका में व्यापार समझौता हो जाता है तो यह व्यापारिक विश्वास को मज़बूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार को +200 बिलियन से ऊपर ले जा सकता है। पिछले कुछ समय में टैरिफ विवाद के कारण कुछ सेक्टर्स (जैसे कृषि उत्पाद, स्टील, वस्त्र) में निर्यात–आयात वृद्धि की गति धीमी हुई। भारत ने अभी से वैकल्पिक बाजारों (जैसे अफ्रीका, यूरोप, ब्रिटेन, आशियान) की ओर ध्यान बढ़ाया है।

भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई बिना सोचे–समझे लिया गया फैसला है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका उद्देश्य एक राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। भारत पर लगाया गया दंडात्मक शुल्क दोनों देशों के बीच पिछले दो दशकों की कड़ी मेहनत से बनाए गए विश्वास और सहयोग को खतरे में डाल रहे हैं। ट्रंप के पुराने सहयोगी भी उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने भारत के साथ टैरिफ प्रकरण पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका ने भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पहले से चले आ रहे प्रयासों को खतरे में डाल दिया है।

भारत–अमेरिका टैरिफ युद्ध ने अल्पावधि में व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा किया है। इस व्यवधान के समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ता, पारदर्शी नीति और संतुलित शुल्क प्रणाली आवश्यक है। इससे भी अधिक बराबरी पर आधारित रिश्ते एवं अमेरिका को खुद को 'विश्व का दरोगा' समझने की चेष्टा को त्यागना होगा। अमेरिका को भारत के प्रति अपना पुराना नज़रिया बदलना होगा तथा विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से विकास के पथ पर बढते नए भारत के साथ समानता के धरातल पर वार्ता करनी होगी। ❑❑

भारत ने नहीं झुकाया सिर, ट्रंप की धमकी को दिया आंकड़ों से करारा जवाब

डोनाल्ड ट्रंप की भारत के प्रति बढ़ती चिढ़ और अमेरिका की दोहरी नीति ने वैश्विक मंच पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को बार–बार टैरिफ और जुर्माने की धमकियां दे रहे हैं, खासकर रूस से तेल और हथियारों के व्यापार को लेकर। लेकिन भारत ने न केवल इन धमकियों को नजरअंदाज किया, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की दोहरी नीतियों को उजागर कर जवाबी रुख अपनाया है। भारत का स्पष्ट कहना है कि जब अमेरिका और यूरोप स्वयं रूस से भारी मात्रा में सामान आयात कर रहे हैं, तो भारत पर रूस के साथ व्यापार को लेकर उंगली उठाना अनुचित और अतार्किक है। यह स्थिति वैश्विक भूराजनीति में दोहरे मानदंडों को उजागर करती है, जहां अमेरिका भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जरूरतों के लिए रूस से व्यापार जारी रखे हुए है।

ट्रंप की बयानबाजी में एक साफ विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वह भारत को "महान मित्र" और "महान देश" कहते हैं, दूसरी तरफ 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से व्यापार के लिए जुर्माने की धमकी देते हैं। उनकी हताशा का कारण यह है कि भारत उनके दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप को लगता है कि जिस भारत को कभी अमेरिका सड़ा हुआ गेहूं भेजता था, वह आज उनकी धमकियों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। उनकी चिढ़ का अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। कभी वह भारत की अर्थव्यवस्था को "मृतप्राय" कहते हैं, तो कभी पाकिस्तान के साथ तेल सौदों की बात कर भारत को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास तेल है ही नहीं, और ट्रंप का यह बयान उनकी हताशा का प्रतीक है। वह भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की रणनीतिक और आर्थिक ताकत के सामने उनकी एक नहीं चल रही।

भारत ने ट्रंप की धमकियों का जवाब न केवल कूटनीतिक रूप से दिया, बल्कि तथ्यों के साथ अमेरिका को आइना भी दिखाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत पर रूस से तेल आयात को लेकर की जा रही आलोचना बेबुनियाद है। भारत ने बताया कि अमेरिका स्वयं रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, खाद, और रसायन जैसे सामान आयात करता है, जो उसकी परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, और कृषि उद्योगों के लिए जरूरी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से मई 2025 तक अमेरिका ने रूस से 2.1 बिलियन डॉलर का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। इसमें पैलेडियम (37 प्रतिशत), यूरेनियम (28 प्रतिशत), और उर्वरक (21 प्रतिशत) का आयात प्रमुख है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस के साथ व्यापार जारी रखा है। 2021 में अमेरिका ने रूस से 17 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था, और 2024 में भी उसने उर्वरक (1.1 बिलियन डॉलर), पैलेडियम (878 मिलियन डॉलर), और यूरेनियम (624 मिलियन डॉलर) जैसे सामानों का आयात किया।

भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में नहीं आएगा और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा।

–अजय कुमार

यूरोपीय संघ भी इस मामले में पीछे नहीं है। वह भारत को रूस से तेल आयात न करने की सलाह देता है, लेकिन स्वयं रूस से ईंधन, लोहा, स्टील, रसायन, और उर्वरक जैसे सामान आयात करता है। 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस से 35.9 अरब यूरो का आयात किया, जिसमें

अमेरिकी विशेषज्ञ भी भारत के साथ टैरिफ युद्ध को गलत मानते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है।

22.3 अरब यूरो का ईंधन प्रमुख था। यह राशि भारतीय रुपये में 3617 करोड़ से अधिक है। भारत का तर्क है कि जब अमेरिका और यूरोप अपनी जरूरतों के लिए रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो भारत पर दबाव डालना दोहरा मापदंड है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से 35–40 प्रतिशत तेल आयात करता है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक ताकत ट्रंप की चिढ़ का प्रमुख कारण है। भारत ने न केवल रूस के साथ व्यापार जारी रखा, बल्कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर जोर दिया, जो दोनों देशों के हितों को संतुलित करे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जवाबी टैरिफ के बजाय बातचीत से समाधान चाहता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी स्पष्ट किया कि भारत ट्रंप के दबाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) के डीजी अजय सहाय के अनुसार, 25 प्रतिशत टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 0.2–0.5 प्रतिशत का असर हो सकता है, लेकिन 6 प्रतिशत से अधिक की विकास दर इसे संभाल सकती है। भारत वैकल्पिक बाजारों जैसे यूरोप, दक्षिण–पूर्व एशिया, और चीन की ओर भी रुख कर रहा है। चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने भारत से आयात बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की बात कही, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है।

ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" और "मेक इन अमेरिका" नीतियां भारत के बिना पूरी तरह सफल नहीं हो सकतीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और विनिर्माण केंद्र है। अमेरिकी कंपनियां जैसे एपल, टेस्ला, और बोइंग भारत में निवेश और उत्पादन बढ़ा रही हैं। ट्रंप के प्रस्तावित 25 प्रतिशत टैरिफ से भारत में बने उत्पाद महंगे होंगे, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा। साथ ही, मेक इन अमेरिका की लागत बढ़ने से अमेरिकी उत्पाद वैश्विक बाजार में चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को यह भी डर है कि भारत यूरोप, चीन, और दक्षिण–पूर्व एशिया जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख कर सकता है, जिससे उसका वैश्विक व्यापार में प्रभाव कम हो सकता है।

अमेरिकी विशेषज्ञ भी भारत के साथ टैरिफ युद्ध को गलत मानते हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि भारत के साथ व्यापारिक तनाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने भारत के साथ संतुलित और पारस्परिक लाभकारी व्यापार वार्ताओं की वकालत की। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ लिसा कर्टिस ने चेतावनी दी कि भारत पर उच्च टैरिफ लगाना अमेरिका की हिंद–प्रशांत रणनीति को कमजोर करेगा और चीन को क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का मौका देगा। अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स भी मानता है कि उच्च टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

ट्रंप की धमकियों के बीच रैपिडान एनर्जी ग्रुप के चेयरमैन बॉब मैकनेली का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत पर रूस से तेल आयात के लिए 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगाई थी ताकि वैश्विक तेल की कीमतें नियंत्रित रहें। पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी का एक वायरल वीडियो भी यही बात दोहराता है। गार्सेटी ने कहा कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वह एक निश्चित मूल्य सीमा पर तेल खरीदे, जिससे वैश्विक बाजार में स्थिरता बनी रहे।

भारत ने इस दोहरे रवैये को उजागर करते हुए साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत 'क्वाड' का प्रमुख स्तंभ है और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति को मजबूती देता है। भारत–अमेरिका पब्म्ज पहल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, और रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ रहा है। भारत की तकनीकी क्षमता और मानव संसाधन अमेरिका के लिए अपरिहार्य हैं। भारत ने अमेरिका के लिए कृषि और डेयरी बाजार पूरी तरह खोलने से भी इनकार किया है, क्योंकि यह 70 करोड़ किसानों के हितों से जुड़ा है।

ट्रंप की बयानबाजी और धमकियां उनकी हताशा का प्रतीक हैं। वह भारत को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही अपनी सामंती मानसिकता के कारण झुकना भी नहीं चाहते। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दबाव में नहीं आएगा और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। आज की तारीख में भारत अमेरिका के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रंप की नीतियां और बयानबाजी अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। भारत ने न केवल अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत का परिचय दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर दोहरे मानदंडों को बेनकाब कर एक नया संदेश भी दिया है। ❑❑

ट्रंप के टैरिफ टेरर से देश को उबारेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और समृद्ध गांव जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने दुनिया के अन्य देशों के साथ–साथ भारत को भी हलकान किया है, लेकिन भारत गांवों का देश है और भारत के गांव हर परिस्थिति में देश को संभालने में सक्षम है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

अमरीकी गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सभी भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी आयात शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। भारत के अलावा ब्राज़ील एकमात्र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार है जिसे 50 प्रतिशत आयात शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। इस घटनाक्रम के बादभारतीय शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली और कमजोर वैश्विक रुझान से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश चाहता है, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। भारत के इनकार के बाद ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को बहाना बनाकर यहां 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क थोपा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका अतिरिक्त शुल्क थोप कर भारत पर कूटनीतिक और व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई समझौता नहीं करेगा क्योंकि भारत के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है। अब भारत आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर मौजूदा चुनौतियों से निपटने की और कदम बढ़ा रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक को सुधारने की बात आर्थिक हलकों में प्रमुखता से रेखांकित की जा रही है।

विश्व भर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने व्यापार शुल्क को लेकर जो हाय–तौबा मची है उससे विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा और मंजिल दोनों को लेकर कई तरह के विमर्श और संकटों की बात हो रही है। यह सारी बातें भविष्य की चिंता से तो जुड़ी ही है, अतीत के अनुभवों को लेकर भी कई एक बातें साफ हुई है। भारत की बात करें तो हमारे यहां खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर उदारीकरण के दौर में जिस तरह की नीतिगत समझ बननी चाहिए थी वैसी नहीं बन सकी थी। इस कारण लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा भारत का ग्रामीण क्षेत्र गंभीर उपेक्षाओं का शिकार रहा। आज जब रोजी रोजगार, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबन की बात प्राथमिकता के साथ बहस के केंद्र में है तो देश के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी आर्थिकी को भी नए सिरे से सुधारने की चिंता संतुलनकारों में दिख रही है।

मालूम हो कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है। शहरीकरण के जोर के बावजूद नीति आयोग का अनुमान है कि 2045 में भी यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर ही रहेगा। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023–24 में बताया गया है कि ग्रामीण रोजगार मुख्य रूप से 54 प्रतिशत स्वरोजगार तथा 26 प्रतिशत आकस्मिक श्रम पर टिका है। ग्रामीण श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (58.5 प्रतिशत) कृषि में लगा हुआ है जो आमतौर पर मौसमी रोजगार ही प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन भोगी नौकरियां कुल कार्य बल का महज 11 प्रतिशत ही है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का सबसे बड़ा आधार वहां के लोगों के आय विकल्पों में सुधार ही है। सुखद है कि इस दिशा में देश की केंद्र तथा राज्य सरकारें सजगता के साथ सकारात्मक कदम बढ़ा रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार का 25 करोड

लोगों को गरीबी से बाहर निकलने का तथ्य जगजाहिर है। इसकी तस्दीक संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कर चुका है। 25 करोड लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने का सबसे चमकदार पक्ष उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे वे राज्य हैं जहां की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। यह दोनों ऐसे राज्य हैं जो बीमारू के नाम पर लंबे दौर तक गांव के पिछड़ेपन के कारण नीची निगाह से देखे जाते रहे हैं। बीते एक दशक में गरीबी उन्मूलन का सर्वाधिक लाभ इन्हीं दोनों प्रदेशों में हुआ है।

गौरतलब है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार की शुरुआत वर्ष 2014 में 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' से हुई थी। इसके तहत अब तक देश में कुल 55 करोड़ से अधिक बैंक खाता खोले जा चुके हैं जिनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। 10 जून 2025 तक इन खातों में कुल जमा राशि 2.51 लाख करोड रुपए से अधिक हो चुकी है। वित्तीय समावेशन की इस कवायद का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बचत और बीमा को लेकर जागरूकता आई है, वहीं वे वित्तीय लाभ के दूसरे विकल्पों को भी अब आसानी से आजमाने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग शेयर बाजार की ओर भी उन्मुख हुए हैं। कोरोना महामारी से पहले डीमैट और म्युचुअल फंड खातों की संख्या 5 करोड़ थी जो अब लगभग बढ़कर 13 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हालांकि इसमें भारी संख्या में भागीदारी शहरी खाता धारकों की है लेकिन माना जा रहा है कि ग्रामीण रुझानों के कारण ही बाजार का आकार बड़ा हुआ है।

देश में शेयर और फंड मार्केट में हिस्सेदारी की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 5 वर्षों में डीमैट खाता धारकों की संख्या के अध्ययन के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा 186 लाख इक्विटी निवेशक

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने दुनिया के अन्य देशों के साथ-साथ भारत को भी हलकान किया है, लेकिन भारत गांवों का देश है और भारत के गांव हर परिस्थिति में देश को संभालने में सक्षम है।

महाराष्ट्र में है जबकि दूसरे स्थान पर 130 करोड़ निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश है। वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में 2025 में महाराष्ट्र में 214.25 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कराई है, वही उत्तर प्रदेश में 471.2 प्रतिशत की छलांग लगाई है। इन सब के बीच इस मोर्चे पर जिस प्रदेश के लोगों में दिलचस्पी जागी है उसका नाम है बिहार प्रदेश। बिहार में वित्तीय वर्ष 2020 में महज 7 लाख बाजार निदेशक थे, पर यह आंकड़ा अब 53 लाख के आसपास पहुंच गया है, यानी 689.2 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर। बिहार में हुए इस युगांतरकारी परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा हाथ बिहार की महिलाओं का है। वर्तमान में बिहार में 6389 जीविका बैंक सखियां ग्रामीणों को बैंक से जुड़े कार्य उनके घर–द्वार पर ही उपलब्ध करा रही हैं।

केंद्र की सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब डाकघर के जरिए भी म्युचुअल फंड खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग और एसोसिएशन आफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के बीच एक करार हुआ है। इस करार का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है यह समझौता 3 वर्ष के लिए हुआ है जो अगस्त 2028 तक लागू रहेगा। सरकार का यह कदम अपनी रूपरेखा और संकल्पना में कितना अच्छा है यह इस बात से समझा जा सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीणों को सुरक्षित और लाभकारी निवेश के प्रति जागरूक करने के लिए सेबी के साथ अभियान की चरणवार रूपरेखा तैयार की है। अभियान के तहत सबसे पहले 6 राज्यों में 3874 मास्टर ट्रेनर का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाने की योजना है। डाकघर के जरिए तमाम तरह की बचत और बीमा सुविधाओं के साथ म्युचुअल फंड की बिक्री शुरू होगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य के ग्रामीण अंचल में समृद्धि और खुशहाली रफ्तार के साथ लौटेगी।

आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और समृद्ध गांव जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने दुनिया के अन्य देशों के साथ–साथ भारत को भी हलकान किया है, लेकिन भारत गांवों का देश है और भारत के गांव हर परिस्थिति में देश को संभालने में सक्षम है। बेशक अमेरिका से निर्यात के मोर्चे पर चुनौती खड़ी हुई है लेकिन भारत के सामने विकल्पों की कमी नहीं है। भारत को अमेरिका से बाहर नए बाजार तलाशने होंगे जिसका काम सरकार के स्तर पर शुरू भी हो चुका है। ऐसे में जरूरी है कि भारत रूस के साथ नई रणनीति के साथ आगे बढ़े और जरूरत पड़ने पर पलटवार की नीति भी अख्तियार करे। भारत तत्काल चुनिंदा वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने की स्थिति में है। प्रभावित क्षेत्रों को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन देकर मजबूत किया जा सकता है। बहरहाल चुनौती बड़ी है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता ग्रामीण भारत में है। ❑❑

(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी रहे हैं)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से पर्यावरण को लाभ कम, जोखिम ज्यादा

हाल के वर्षों में, एआई ने जटिल समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारी लोकप्रियता हासिल की है, बीमारियों के निदान से लेकर बाढ़ के पूर्वानुमान तक। जलवायु संकट को संबोधित करने में इसकी क्षमता भी प्रशंसनीय है – उदाहरण के लिए, पर्यावरण अनुसंधान की सहायता में, जिसने वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव की मैपिंग में योगदान दिया है, साथ ही साथ सूखे और जंगल की आग का पूर्वानुमान लगाया है। कार्यकर्ता अब ग्लोबल फिशिंग वॉच का उपयोग कर रहे हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों में ओवरफिशिंग और अवैध मछली पकड़ने की पहचान करने के लिए मशीन–लर्निंग सॉफ्टवेयर को नियुक्त करता है, जिससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा होती है। हालांकि, इस सब उत्साह के पीछे, एक असहज सच है – एआई पर्यावरण के लिए अच्छे से अधिक नुकसान कर सकता है।

एआई की लाभ समस्या

एआई के उदय ने व्यवसायों के लिए अपने मुनाफे को अधिकतम करने के कई अवसर खोले हैं, लेकिन यह एक कीमत पर आता है। व्यवसाय तेजी से एआई पर भरोसा करते हैं, जिससे संसाधन निष्कर्षण, औद्योगिक उत्पादन और वैश्विक खपत में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, बड़े निगमों द्वारा बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक डेटासेट का विश्लेषण करने के लिए गहरी शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य नए तेल और गैस भंडार की पहचान करना है। इसके अतिरिक्त, एआई के नेतृत्व में स्मार्ट सबमर्सिबल, अब समुद्र के दूरदराज के हिस्सों में अप्रयुक्त तेल और गैस भंडार का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा, लाभ उत्पन्न करने के लिए, राज्य और फर्म अक्सर अपनी पर्यावरणीय लागतों को

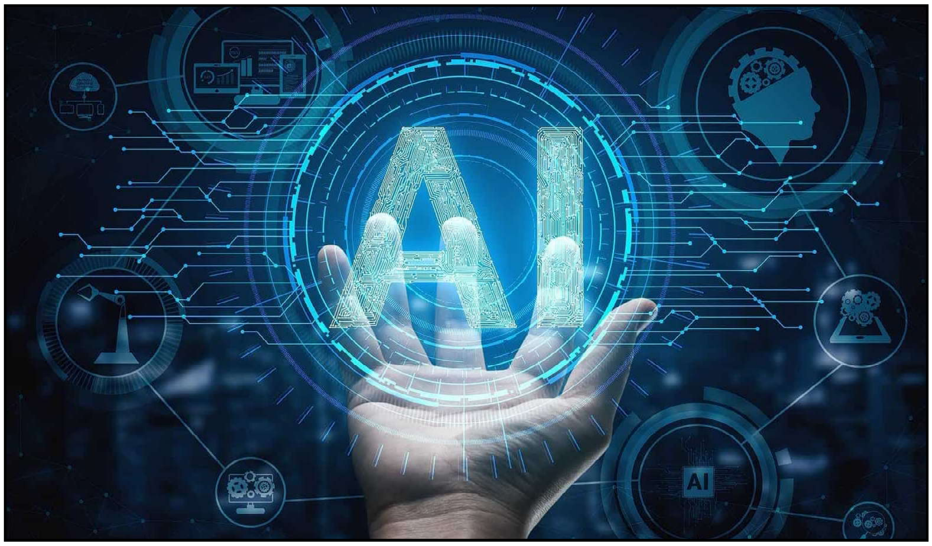

उचित विनियमन के बिना, एआई ओवरप्रोडक्शन और अस्थिर खपत का एक उपकरण बन सकता है।
–**स्वदेशी संवाद**

कम करते या छिपाते हुए, व्यक्तिगत लाभ के लिए नई एआई तकनीक के लाभों को अतिरंजित करते हैं। तकनीकी दुनिया लोगों को हाइपिंग करके काम करती है – उदाहरण के लिए, जब स्टार्ट–अप निवेशकों से धन आकर्षित करने के लिए 'तकनीकी सफलताओं' का दावा करते हैं। अमेज़ॅन और गूगल जैसी बड़ी फर्म इस स्थान पर हावी हैं, प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करती हैं और सार्वजनिक धारणा को आकार देती हैं। परिणाम? ग्रह के पहले से ही सीमित संसाधनों पर उत्पादन, अधिक खपत और बढ़ते दबाव में वृद्धि।

एआई का अपना पर्यावरण पदचिह्न

एआई न केवल पर्यावरणीय रूप से हानिकारक प्रथाओं की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि संसाधन–गहन भी है। उन्नत आई मॉडल, जैसे कि चैटजीपीटी और जैन आई को प्रशिक्षित करने के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, चैटजीपीटी के माध्यम से की गई एक खोज एक साधारण गूगल खोज की तुलना में दस गुना अधिक ऊर्जा की खपत करती है। सहज रूप से, जटिल मॉडल और भी अधिक ऊर्जा–गहन होते हैं और समग्र पर्यावरणीय पदचिह्न पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

इसके अलावा, एक बार एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के बाद, ऊर्जा की मांग बंद नहीं होती है; बल्कि, यह हर बार उपयोग किए जाने पर बिजली का उपभोग करना जारी रखता है। एआई के उदय ने डेटा केंद्रों के विस्तार को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें उपकरणों को ठंडा करने और ओवरहीटिंग को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। वे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन भी करते हैं और महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। जैसे–जैसे कंपनियां लगातार नए और अधिक शक्तिशाली मॉडल जारी करती हैं, कार्बन उत्सर्जन उस गति से बढ़ता जा रहा है जो एआई उपकरण को कम करने में मदद कर सकता है।

एआई के जोखिमों को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका पर्यावरण संकटों के अभिनव समाधान प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई विकास पर्यावरण और सामाजिक लक्ष्यों के साथ गठबंधन है, राजनीति के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ना है।

स्मार्ट टेक की जरूरत है स्मार्ट गवर्नेंस

यदि अकेले निगमों में छोड़ दिया जाता है, तो एआई को अल्पकालिक मुनाफे के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षरण होता है। उचित विनियमन के बिना, एआई ओवरप्रोडक्शन और अस्थिर खपत का एक उपकरण बन सकता है। इसलिए, मेरा मानना है कि एआई के जोखिमों को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका पर्यावरण संकटों के अभिनव समाधान प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई विकास पर्यावरण और सामाजिक लक्ष्यों के साथ गठबंधन है, राजनीति के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ना है।

सरकार को जनहित के लिए इसके उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए एआई विकास को अधिक बारीकी से नियंत्रित करना चाहिए, विशेष रूप से शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और जलवायु और स्थिरता पर काम करने वाले संस्थानों के बीच। इसके अतिरिक्त, राज्य–वित्त पोषित एआई पहल कम–कार्बन प्रौद्योगिकियों के साथ उद्योगों को बदलने में मदद कर सकती है, जबकि व्यवसायों को विशुद्ध रूप से लाभ–संचालित उद्देश्यों के लिए इन प्रौद्योगिकियों का अधिक उपयोग करने से भी रोक सकती है। आज की दुनिया में, हम प्रौद्योगिकी के निष्क्रिय रिसीवर नहीं हैं; बल्कि, हमारे पास इसे जिम्मेदारी से अपने लाभ के लिए आकार देने की शक्ति है। इसलिए, हमें सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसके उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना चाहिए। ❑❑

(विजय गर्ग की कलम से)

भारतीय दर्शन में है वैश्विक समस्याओं का हल

आज हमें अपने सिद्धांतों के आधार पर मौलिक चिंतन करना चाहिए। हम दुनिया भर के विचार प्रवाहों को परखेंगे तथा अपनी स्वतंत्र मौलिक राष्ट्रीय चिंतनधारा के अनुरूप अपना रास्ता अपनाएंगे।

–प्रहलाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर आज की आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत का प्राचीन आर्थिक दर्शन संभवतः आशा की किरण के रूप में दिखाई पड़ता है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, अपने अहंकार के मद में, जब अपने पड़ोसी देशों एवं हितचिंतक देशों के साथ ही अन्य अविकसित एवं विकासशील देशों को भी नहीं बख्श रहा है एवं इन देशों से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर टैरिफ का डंडा चला रहा है, तब भारतीय आर्थिक दर्शन यथा– "वसुधैव कुटुंबकम", "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" एवं "सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामयाः" जैसी नीतियों की याद सहज रूप से ही आ जाती है। भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, अर्थ का अर्जन करना बुरी बात नहीं है परंतु इसका धर्म के अनुसार उपयोग नहीं करना बुरी बात है। ट्रम्प प्रशासन की वर्तमान नीतियों से स्पष्ट झलकता है कि अथाह मात्रा में इकट्ठे किए गए धन का उपयोग विश्व के अन्य देशों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका आज कई देशों पर दबाव बनाता हुआ दिख रहा है कि यदि किसी देश ने उसकी शर्तों के अनुरूप अमेरिका के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौता नहीं किया तो उस देश से होने वाले वस्तुओं के अमेरिका में आयात पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाया जाएगा।

यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्व के कई देश विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े हैं और सम्पन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इन देशों के नागरिकों को भौतिक सुख की प्राप्ति तो हुई है परंतु उनके जीवन में मानसिक सुख का पूर्णतः अभाव है। अतः इनके जीवन में संतोष का अभाव है और यह लोग कुंठा की भावना में बहते हुए कुछ इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जिससे समाज के अन्य लोगों का अहित हो रहा है। समाज के अन्य नागरिकों की स्थिति कैसी है, इस बात पर उनका ध्यान बिलकुल नहीं है। अपने को अधिक धनवान बनाने की प्रक्रिया में वे अपने ही समाज के नागरिकों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। आज अमेरिका की स्थिति भी लगभग यही है। आज वह पूरे विश्व की चौधराहट प्राप्त करने के प्रयास में कुछ इस प्रकार की नीतियों का अनुपालन करता हुआ दिखाई दे रहा है जो अन्य देशों का नुकसान कर सकती हैं। परंतु, अन्य देशों को होने वाले नुकसान के प्रति अमेरिका आज पूर्णतः अनजान सा बना हुआ है। पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति डावांडोल होती हुई दिखाई दे रही है। यह सब तब हो रहा है जब विश्व की बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भूख, गरीबी एवं बेकारी से त्रस्त है। समाज का एक वर्ग अमीर से और अधिक अमीर हो रहा है तो समाज का दूसरा वर्ग गरीब से और अधिक गरीब हो रहा है। आय की असमानता की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। कुल मिलाकर अमेरिका सहित विश्व के कई विकसित देशों के नागरिक आज अपनी आर्थिक तरक्की से संतुष्ट नहीं है एवं भौतिक सुख होने के बावजूद मानसिक बीमारियों से ग्रस्त नजर आ रहे हैं।

हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का इस धरा पर जन्म, परेशानियाँ झेलने के लिए नहीं हुआ है। बल्कि, इस मानव जीवन को समस्याओं रहित बनाकर, शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए हुआ है। आज विभिन्न देशों के नागरिक खाने पीने की वस्तुओं, अच्छे वस्त्रों, बड़े एवं सुविधाजनक निवास स्थान, मनोविनोद के साधनों में वृद्धि, वासना की वृद्धि एवं वासना की संतुष्टि के लिए विभिन्न साधनों में वृद्धि, सुख के लिए उपभोग में वृद्धि जैसे कार्यों पर

अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। जैसे इस धरा पर जीवन जीने का लक्ष्य यही है। इच्छाओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह पूंजीवाद में निहित पश्चिमी विचार है। इस धारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) कहते हैं कि ''पश्चिम के सुख की अवधारणा पूर्णतया प्रकृति जन्य इच्छाओं की संतुष्टि पर केंद्रित है, अतः उनके जीवन स्तर को उठाने का अर्थ भी केवल भौतिक आनंद की वस्तुओं को अधिकाधिक जुटाना है। इससे व्यक्ति अन्य विचारों एवं एषणाओं को छोड़कर केवल इसी में पूर्णतया संलग्न हो जाता है। भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की इच्छा धन संग्रह को जन्म देती है। अधिकाधिक धन प्राप्ति हेतु शक्ति आवश्यक हो जाती है; किंतु भौतिक सुख की अतृप्त क्षुधा व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं तक ही नहीं रुकने देती। सबल राष्ट्र, राज्य शक्ति के आधार पर दूसरों के दमन व शोषण का भी प्रयास करते हैं। इससे संघर्ष व विनाश का जन्म होता है। एक बार यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। सभी नैतिक बंधन विच्छिन हो जाते हैं। सामान्य मानवीय संवेदनायें सूख जाती हैं। मनुष्य और पशु में अंतर स्थापित करने वाले मूल्य एवं गुण समाप्त हो जाते हैं।'' हालांकि उक्त विचार आज से लगभग 65–70 वर्ष पूर्व व्यक्त किए गए थे परंतु यह आज अमेरिका की स्थिति पर सटीक बैठते हैं। ''मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'' के नारे के साथ सत्ता में आने वाले डोनाल्ड ट्रम्प आज पूरे विश्व में अराजकता की सत्ता स्थापित करने में लगे हुए हैं। केवल और केवल अमेरिका के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देना है, इससे अन्य राष्ट्रों

भारतीय आर्थिक चिंतन पश्चिम के आर्थिक चिंतन के ठीक विपरीत है। हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार, अर्थ एवं भोग को धर्म के अनुसार ही कार्यशील रखना चाहिए।

(अविकसित एवं विकासशील देशों सहित) का कितना भी नुक्सान हों परंतु अमेरिकी उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के हित सुरक्षित रहने चाहिए, उनकी आर्थिक तरक्की होते रहना चाहिए।

भारतीय आर्थिक चिंतन पश्चिम के आर्थिक चिंतन के ठीक विपरीत है। हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार, अर्थ एवं भोग को धर्म के अनुसार ही कार्यशील रखना चाहिए। इस संदर्भ में संयम को प्राथमिकता दी गई है। कोई भी कार्य, सीमा के अंदर किया जाय तो उचित होता है। सीमा के बाहर जाकर किया गया कार्य, समाज में अस्थिरता प्रतिपादित कर सकता है। अत्यधिक भोग का भारतीय संस्कृति में निषेध है। अर्थ के अधिक मात्रा में अर्जन पर हालांकि किसी प्रकार का निषेध नहीं है परंतु अर्थ के उपभोग पर जरूर कुछ सीमाएं निर्धारित हैं। अर्थ का उपयोग स्वयं की सुख प्राप्ति के लिए उपभोग करने के उपरांत परिवार, समाज, धर्म की रक्षा, संस्कृति के विस्तार, भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत, आदि के लिए करना आवश्यक माना गया है। पश्चिमी सभ्यता के अनुसार तो अर्थ का उपभोग केवल एवं केवल स्वयं के लिए किया जाता है एवं येन केन प्रकारेण व्यक्ति द्वारा इसकी वृद्धि हेतु प्रयास किए जाते हैं। सुख को तो अपने अंदर महसूस किया जा सकता है। बाहरी भौतिक आवरण पहनकर सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं है। इसी संदर्भ में श्री गुरुजी कहते हैं कि ''सब बातों का विचार हमारे पूर्वजों ने भी किया था। समय पर वर्षा होना चाहिए, पृथ्वी पर धन धान्य की समृद्धि रहना चाहिए, समाज को ऐच्छिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होना चाहिए, कोई भी दुखी न रहे – ऐसी प्रार्थना उन्होंने की है, परंतु उस समय भी उनको अनुभव हुआ कि मनुष्य केवल वासनाओं का पुतला नहीं है। वासनाओं की तुष्टि कुछ समय के लिए आनंद देती हैं, किंतु हमेशा के लिए वह आनंद नहीं दे सकती। मनुष्य तो ऐसा सुख चाहता है, जो कभी क्षीण न हो, उसमें कभी बाधा न आ सके, यानी वह अबाधित, नित्य सुरक्षित और चिरकालिक सुख की कामना करता है''।

उक्त विचार को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरुजी कहते हैं कि ''अपनी भारतीय प्रणाली में जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, उसमें आज जैसा केवल आर्थिक पहलू मात्र नहीं था। हमारे यहां अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम नीतिशास्त्र था। आज हमें अपने सिद्धांतों के आधार पर मौलिक चिंतन करना चाहिए। हम दुनिया भर के विचार प्रवाहों को परखेंगे तथा अपनी स्वतंत्र मौलिक राष्ट्रीय चिंतनधारा के अनुरूप अपना रास्ता अपनाएंगे। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में संपत्ति के विकेंद्रीकरण के लिए ट्रस्टीशिप का मार्ग प्रतिपादित किया। उनके इस ट्रस्टीशिप के विचार में माना गया है कि मनुष्य के उत्पादन सामर्थ्य में कोई कमी करने की जरूरत नहीं जीविका के साधनों द्वारा जितना चाहे, उसे उत्पादन करने दो, परंतु संग्रह का वह अधिकारी नहीं है। जीविका के साधनों का प्रयोग करने पर जो संपत्ति एकत्रित होती है, वह समाज की है, अपने उपभोग बढ़ाने के लिए नहीं। वह सम्पत्ति उसने समाज को दे देनी चाहिए।'' कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय आर्थिक दर्शन में ट्रम्प प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। ❑❑

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पांच वर्ष

नीति से अभ्यास तक

शिक्षा और इससे संबंधित ज्ञान प्रतिमान प्रगतिशील समाजों की नींव रहे हैं। भारतीय छात्रवृत्ति का एक समृद्ध प्राचीन भंडार दुनिया भर में स्वीकार किया गया है और कई को अपने संबंधित शैक्षणिक क्षेत्रों में योगदान करने के लिए प्रेरित किया है।

इस तरह की शानदार ज्ञान विरासत के बावजूद, इस राष्ट्र को वर्ष 2020 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने में 73 साल लगे, जो भारत की ज्ञान परंपराओं और मूल्य प्रणालियों के निर्माण के दौरान 21 वीं शताब्दी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के साथ गठबंधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) 29 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी उसके पांच साल पूरे हो रहे हैं।

यह हमें नीति के कार्यान्वयन का समग्र दृष्टिकोण लेने, अनुकूल परिवर्तनों का आकलन करने, स्कूल में समग्र प्रगति और उच्च शिक्षा के साथ–साथ सुधार की आगे की गुंजाइश की अनुमति देता है।

शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा विषयों की वैचारिक स्पष्टता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षाविदों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की वकालत की है। स्वतंत्रता के बाद, डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट (दिसंबर 1948–अगस्त 1949) में शिक्षा पर शुरुआती सिफारिशों में से एक में कहा कि अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं द्वारा व्यावहारिक रूप से जल्द निर्देश के माध्यम से रूप में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

हालांकि, इस सिफारिश ने केवल उस दिन की रोशनी देखी जब एनईपी 2020 ने सिफारिश की कि 'कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक' मूल भाषा में होना चाहिए। भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता पिछले पांच वर्षों में एक सतत अभ्यास रही है।

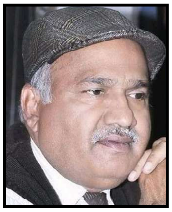

एनईपी 2020 ने इसके कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों के भीतर प्रणालीगत शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार पेश किए हैं।

– विजय गर्ग

दो साल पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एनईपी 2020 के अनुरूप 12 भारतीय भाषाओं में 100 किताबें लॉन्च की थीं। दिशाख (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) एक राष्ट्रीय वेब प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग शिक्षा ई–इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में किया जाता है, जहां 31 भारतीय भाषाओं के लिए ऊर्जावान पुस्तकें (जो एक क्यूआर कोड के साथ आती हैं) और 7 विदेशी भाषाएं तैयार की जा रही हैं।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना के लिए 2025–26 बजट आवंटन भारतीय भाषाओं में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकें प्रदान करने के लिए संस्थानों को पाठ्यक्रम में शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 2011 की जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि 96.71 प्रतिशत नागरिकों ने अपनी मातृभाषा के रूप में बाईस अनुसूचित भाषाओं में से एक को चुना है, जबकि केवल 10.6 प्रतिशत ने कहा कि वे अंग्रेजी बोल सकते हैं।

एक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं में शिक्षा, शिक्षा को अधिक समावेशी बनाएगी और आने वाले वर्षों में सीखने के परिणामों को बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में

स्थित पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज में, बी. टेक छात्रों को पूरी तरह से मराठी में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग सिखाया गया था। उन्होंने शीर्ष कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि भाषा तकनीकी शिक्षा में सफलता के लिए कोई बाधा नहीं है।

नई शिक्षा नीति के तहत हमारी पाठ्यपुस्तकों में औपनिवेशिक हैंगओवर के बोझ को अंततः भारतीय योगदान द्वारा बदल दिया गया है।

भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना एनईपी 2020 की प्राथमिक चिंताओं में से एक है। यह एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान बनाने पर जोर देता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कक्षा पांच और आठ के लिए दस नई पाठ्यपुस्तकें शुरू की हैं, जो भाषाओं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और कला शिक्षा को कवर करती हैं। अधिक वैचारिक समझ, शैक्षणिक दृष्टिकोण और अनुभवात्मक सीखने पर जोर दिया गया है। एनईपी के तहत, हमारी विरासत में पाठ्यपुस्तकों को जड़ से जोड़ देना एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है जिसका उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है।

एनईपी 2020 ने पाठ्यक्रम में 21 वीं शताब्दी के हाथों के अनुभव और कौशल आवश्यकताओं के समावेश की भी परिकल्पना की है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क द्वारा अकादमिक और कौशल–आधारित सीखने की समानता और एकीकरण सुनिश्चित करने वाले नियामक ढांचे को औपचारिक रूप दिया गया है। यह समानता और शैक्षणिक कार्यक्रमों में समानता, विशेष रूप से तृतीयक शिक्षा में, एक एकीकृत क्रेडिट प्रणाली में निर्बाध हस्तांतरण में सहायता करेगा।

उच्च शिक्षा में एक कार्यक्रम में एक छात्र के लिए कई प्रवेश–निकास विकल्पों ने शैक्षणिक लचीलापन पेश किया है। देशव्यापी छात्रों की शैक्षणिक साख को सुव्यवस्थित करने के लिए, स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री नामक छात्रों के लिए एक अद्वितीय 12–अंकीय आईडी उत्पन्न की जा रही है जो डिजिटल रूप से शैक्षणिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करती है और उन्हें अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में संग्रहीत करती है। यह प्रौद्योगिकी–सहायता प्राप्त रिकॉर्ड प्रबंधन पूरे देश में पहुंच और निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' अभियान का समर्थन करता है।

एनईपी 2020 के पांच साल ने देश में शिक्षा प्रणाली में एक कट्टरपंथी परिवर्तन लाया है। अगले पांच वर्षों में इसके कार्यान्वयन में छलांग लेने का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में संकाय का क्षमता निर्माण होगा। वर्तमान में, निशंक (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) और (मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम) क्रमशः स्कूलों और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। शिक्षकों को अनुभवात्मक सीखने और योग्यता–आधारित आकलन जैसे नए शैक्षणिक तरीकों से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। भौतिक मोड में मजबूत पेशेवर विकास कार्यक्रम एनईपी 2020 की निष्पादन गति को कैस्केड कर सकते हैं। देश में विभिन्न शिक्षा नीतियों में एक निरंतर विशेषता, कोठारी आयोग (1965) से एनईपी (2020) तक, शिक्षा के लिए जीडीपी का 6 प्रतिशत का बजटीय प्रावधान रहा है।

शिक्षा मंत्रालय की 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए मिलकर जल्द से जल्द जीडीपी के 6 प्रतिशत के ऊपर तक पहुंच जाएंगे। शिक्षा, संविधान में एक समवर्ती विषय होने के नाते, केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों से भी हाथ मिलाने की आवश्यकता है।

केंद्र द्वारा समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहल का उद्देश्य मौजूदा प्रणालियों, स्तर के प्रदर्शन, सीखने के परिणामों और स्कूल स्तर पर लिंग अंतराल को बेहतर बनाना है। हालांकि, राज्य सरकारें महत्वपूर्ण हितधारक हैं, और उनकी राजनीतिक कारणों और इच्छाशक्ति की कमी से लक्ष्यों तक पहुंचने में संभावित अंतराल हो सकता है।

एक मानकीकृत निगरानी तंत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी मूल्यांकन और कार्यान्वयन में मदद कर सकता है। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक (एफएलएन) और बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में। राज्यों द्वारा नीति के साथ जुड़ाव का अलग–अलग स्तर और कई बार देश का सरासर आकार, एनईपी 2020 की वर्दी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक चिंता का विषय है।

एनईपी 2020 ने इसके कार्यान्वयन के पहले पांच वर्षों के भीतर प्रणालीगत शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार पेश किए हैं। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की तैयारी करने वाले राष्ट्र के रूप में, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन भारत की बौद्धिक और कौशल पूंजी और आर्थिक शक्ति को आकार देने में महत्वएनईपीपूर्ण भूमिका निभाएगा।

देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन उन नागरिकों को तैयार करेगा जो भारतीय होने पर गर्व करते हैं। ईंधन नवाचार करते हैं, एक ज्ञान अर्थव्यवस्था विकसित करते हैं, इक्विटी, सतत विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं और आत्मविश्वास से दुनिया के साथ जुड़ने के लिए सुसज्जित होंगे। ❑❑

षड्यंत्र था भगवा आतंक का जुमला

भारतीय न्यायिक इतिहास में मालेगांव बम धमाकों (2008) से जुड़ा फैसला मील का पत्थर माना जाएगा। इसने भगवा आतंक के मिथ्या आख्यान को ध्वस्त किया। इस्लामिक आतंक की विष बेल की धारणा को संतुलित करने के लिए ही भगवा या हिंदू आतंक का फर्जीवाड़ा किया गया। इसे स्थापित करने के लिए कई कड़ियां भी जोड़ी गईं, लेकिन जांच और अदालती फैसले ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। हिंदू आतंक के फर्जीवाड़े की हवा समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के साथ ही फैली थी। दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 18 फरवरी, 2007 को पानीपत में बम धमाकों की शिकार बनी। इसमें 68 लोग मारे गए। कथित हिंदू आतंक के मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और स्वामी असीमानंद को फंसाने का कुचक्र रचा गया। आरोप लगाया गया कि धमाकों के लिए पुरोहित ने 60 किलो आरडीएक्स चुराया, पर यह तब निराधार निकला, जब पता चला कि बम बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट सल्फर आदि का इस्तेमाल किया गया था। तब अमेरिकी एजेंसियों की जांच में यह सामने आया था कि मुंबई ट्रेन धमाकों और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तानी आतंकी आरिफ कसमानी का हाथ था, जबकि मक्का मस्जिद धमाका हरकत–उल–जिहाद–इस्लामी (हूजी) ने किया था। लश्कर आतंकी कसमानी ने मुंबई धमाकों के लिए दाऊद इब्राहिम से पैसे जुटाए थे। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में उसे आतंकी घोषित किया।

मालेगांव में पहले धमाके 8 सितंबर, 2006 को हुए, जिनमें 30 से अधिक लोग मरे। महाराष्ट्र एटीएस ने सिमी और लश्कर के नौ लोगों को आरोपित बनाया। कुछ दलों और अल्पसंख्यक नेताओं के दबाव में यह मामला सीबीआइ को सौंपा, जो बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए के पास गया। एनआइए ने दावा किया कि मालेगांव धमाके, हैदराबाद, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस जैसे आतंकी हमले हिंदुओं ने किए, जो जिहादी आतंक से बदला लेना चाहते थे। एनआइए ने 22 मई, 2013 को आरोप–पत्र में प्रज्ञा और स्वामी असीमानंद को मुख्य आरोपित बनाया। चूंकि उनके विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य नहीं थे, इसलिए प्रज्ञा और पुरोहित का संदर्भ नहीं दिया और उन्हें 2008 मालेगांव धमाकों में आरोपित बनाया गया।

अब हिंदू आतंक के फर्जी विमर्श की धज्जियां उड़ चुकी हैं।
–संध्या जैन

मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को हुए कम तीव्रता वाले धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल कथित रूप से साध्वी प्रज्ञा की बताई गई, जो कि बाइक सुनील जोशी को बेच दी गई थी, पर स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जोशी की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्रज्ञा और पांच अन्य को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने 19 जनवरी, 2009 को दाखिल चार्जशीट में पुरोहित और प्रज्ञा को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया। पुरोहित पर विस्फोटक उपलब्ध कराने और प्रज्ञा पर धमाके करने के लिए लोगों को जुटाने का आरोप लगाया। ये आरोप टिक नहीं पाए। सितंबर 2017 में जमानत मिलने के बाद पुरोहित ने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि एक दल के मुखिया इस षड्यंत्र के पीछे हैं। धमाकों के समय वे तो खुफिया जानकारियां जुटाने के सिलसिले में पचमढ़ी में एक कोर्स कर रहे थे। माना जाता है कि

नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर वे कुछ ऐसी जानकारियां हासिल कर रहे थे, जो उनकी परेशानियों का कारण बन गईं। इस मामले में कर्नल आरके श्रीवास्तव का नाम भी एक अहम कड़ी है। भोपाल एयरपोर्ट पर कर्नल श्रीवास्तव ने पुरोहित को एक फर्जी आवाजाही आदेश के तहत मुंबई की उड़ान पकड़ने पर मजबूर किया। सैन्य अदालत द्वारा 2009 की जांच में पुरोहित के इस दावे पर मुहर लगी कि कर्नल श्रीवास्तव ने उन्हें अगवा कर अवैध रूप से कब्जे में रखा। पुरोहित को खंडाला के एक बंगले में 4 नवंबर, 2008 तक एटीएस की अवैध कस्टडी में रखा गया, जहां उन्हें भयंकर शारीरिक–मानसिक यातनाएं दी गईं। इस मामले में जिन अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका रही, उनमें एक एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे थे, जिनकी मुंबई आतंकी हमले में मौत हो गई थी। तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक परमबीर सिंह, इंस्पेक्टर अरुण खानविलकर और असिस्टेंट कमिश्नर मोहन कुलकर्णी भी इनमें शामिल माने गए। पुरोहित को 2008 के मालेगांव धमाकों में आरोपित नंबर नौ बनाया गया। पचमढ़ी से पहले पुरोहित सेना की दक्षिणी कमान, पुणे की एक ईकाई से जुड़े थे। उनके आधिकारिक खुफिया सूत्र सुधाकर चतुर्वेदी को मालेगांव मामले में आरोपित नंबर 11 बनाया गया।

एटीएस के अनुसार मालेगांव धमाकों में इस्तेमाल आरडीएक्स के तार चतुर्वेदी जुड़े थे। सेना की जांच में पता चला कि चतुर्वेदी की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले एटीएस अधिकारी शेखर बागड़े को चतुर्वेदी के घर में यह सुबूत प्लांट करते हुए पकड़ा गया। समझौता एक्सप्रेस की तरह 2008 मालेगांव धमाकों में भी आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था।

2013 में केंद्रीय सूचना आयोग के दबाव में सैन्य प्राधिकारी संस्थाओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्हें पुरोहित से यह खुफिया जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में नकली करेंसी का नेटवर्क चल रहा है, जिसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हैं। चूंकि पुरोहित कुछ ऊंचे लोगों की करतूतों का भंडा फोड़ कर सकते थे, इसलिए उन्हें फंसा दिया गया । पुरोहित की तरह प्रज्ञा को भी बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि औपचारिक गिरफ्तारी से पहले अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। उनके नार्को और पालीग्राफ टेस्ट में किसी अपराध की पुष्टि नहीं हुई। उन्हें फंसाने के लिए एटीएस ने 2006 और 2008 धमाकों के तथ्यों का घालमेल कर दिया। इसके बाद हुए मुंबई आतंकी हमले को भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2010 में शर्मनाक रूप से 'आरएसएस की साजिश' करार दिया। इस फर्जी विमर्श की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ❑❑

(स्तंभकार वरिष्ठ पत्रकार, शोधकर्ता एवं लेखिका हैं)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है पीओके

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–कश्मीर (पीओजेके) को भारत से फिर जोड़ने की मांग उठने लगी थी। फिर इस मुद्दे को संसद में भी व्यापक रूप से उठाया गया। सामान्य रूप से इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुखर रही है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीओजेके के भारत में अधिमिलन को लेकर लगातार अपनी बात रखते आए हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस पहली बार पीओजेके का मुद्दा उठा रही है।

दरअसल, एक लंबे समय तक कांग्रेस ने पीओजेके को कभी गंभीरता से नहीं लिया। दशकों तक यह कांग्रेस की प्राथमिकताओं में भी शामिल नहीं हुआ. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ने पहली बार, भले ही केवल राजनीतिक स्तर पर सही, पीओजेके को लेकर सार्वजनिक तौर पर चर्चा शुरू की, किन्तु इस प्रक्रिया में कांग्रेस के नेता कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना भूल गए अथवा जानबूझकर अनजान बने रहे।

पीओजेके की जो वर्तमान स्थिति है वह कांग्रेस की पूर्ववर्ती नीतियों और लम्बे अंतराल तक साधी गई चुप्पी का परिणाम है। इसलिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस भारतीय भूभाग को फिर एकबार भारत में मिलाना पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और सामरिक चुनौतियों से परिपूर्ण हो गया है।

– देवेश खण्डेलवाल

पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख

वास्तव में, पीओजेके की जो वर्तमान स्थिति है वह कांग्रेस की पूर्ववर्ती नीतियों और लम्बे अंतराल तक साधी गई चुप्पी का परिणाम है। इसलिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इस भारतीय भूभाग को भारत में मिलाना पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और सामरिक चुनौतियों से परिपूर्ण हो गया है। हम जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर रियासत पर सशस्त्र हमला किया, तब भारत ने भी सैन्य प्रतिकार से उसका जवाब दिया।

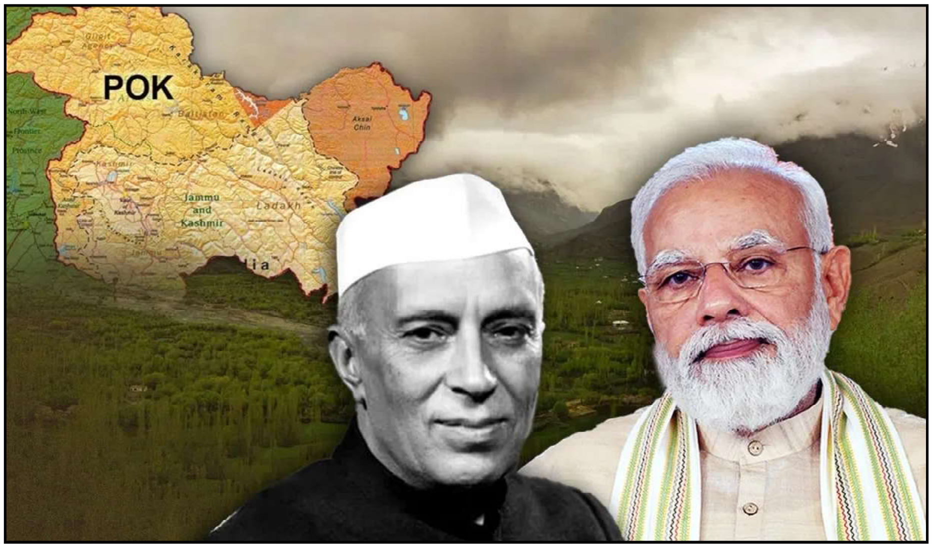

भारतीय सेना ने अधिमिलन के तत्पश्चात पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। परंतु उसी समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नर–जनरल माउंटबेटन की सलाह पर पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख किया। जिसके बाद युद्धविराम की घोषणा की गयी, जिससे भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान की सेना के कब्जे वाला भूभाग पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–कश्मीर यानि पीओजेके बन गया।

पीओजेके पर भारत के दावे की स्थिति कमजोर

बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को भी स्वयं आभास हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील करना एक ऐतिहासिक भूल थी। मगर इससे सबक लेने के स्थानपर गलतियों की लम्बी श्रृंखला शुरू की गयी और अंत में पीओजेके पर भारत के दावे की स्थिति को कमजोर बना दिया गया। जब–जब कांग्रेस सत्ता में रही, तब–तब इस मुद्दे पर उसकी उदासीनता, और निर्णयहीनता उजागर होती रही. एक के बाद एक कूटनीतिक और सामरिक भूलें होती गईं, जिनका खामियाज़ा आज पूरा देश भुगत रहा है।

1957 में भारत के पास था बड़ा अवसर

साल 1957 में भारत के पास एक बड़ा अवसर था, जब मंगला बांध के निर्माण को लेकर मीरपुर और हवेली क्षेत्र में पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध जबर्दस्त जनविरोध फूट पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्शल लॉ थोप दिया और 5,000 से अधिक निर्दोष लोगों को गिरफ़्तार कर यातनाएं दी गईं। स्थिति भयावह हो गई, नागरिक भूख से मरने लगे, और पाकिस्तानी सेना से त्रस्त होकर सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर भारत आने लगे। इस घटनाक्रम में एक नाम विशेष रूप से उभरा – सजदा बेगम, जो एक पाकिस्तानी पत्रकार की पत्नी थीं और जान बचाकर भारत आ पहुंचीं. उस समय उनकी कहानी अखबारों की सुर्खियां बनीं।

भारत सरकार ने गंवा दिया मौका

दुर्भाग्यवश, यह मौका भारत सरकार की एक कूटनीतिक विफलता के रूप में दर्ज हुआ। न तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार उल्लंघनों के इस गंभीर प्रकरण को पर्याप्त रूप से उठाया, और न ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर अपने वैधानिक दावे को दोहराने का कोई ठोस प्रयास किया। कुल मिलाकर, भारत सरकार ने उस ऐतिहासिक अवसर को बिना किसी रणनीतिक लाभ के गंवा दिया।

1970 में भी हुए विरोध–प्रदर्शन

पीओजेके में पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध साल 1970 में भी व्यापक विरोध–प्रदर्शन हुए थे। तब पहली बार पाकिस्तानी समाचार–पत्रों ने उन प्रदर्शनों को खुलकर प्रकाशित किया था। किंतु तब भी तत्कालीन भारत सरकार हस्तक्षेप करने में असफल रही और फिर एक महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकाल दिया। इसी बीच साल 1964 में खबर आई की पाकिस्तान ने बीजिंग तक सड़क निर्माण की योजना बनाई है। मुद्दा राज्यसभा में भी उठा, मगर तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने बताया कि यह विषय सरकार के ध्यान में है लेकिन हस्तक्षेप करने की हर संभावना से इनकार कर दिया।

चीन–पाकिस्तान के गठजोड़ पर हंगामा

साल 1983 में भी चीन–पाकिस्तान के इस गठजोड़ पर राज्यसभा में हंगामा मचा लेकिन तत्कालीन विदेश मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने सिर्फ इतना कहा कि इससे देश की सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे, इसलिए हम इस मुद्दे पर नजर रख रहे हैं। साल 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि गिलगित–बाल्टिस्तान में 7–11 हजार चीनी सैनिक तैनात है। सामरिक रूप से चीन ने पीओजेके के कई हिस्सों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। मगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारें अपने अलग–अलग कार्यकालों में निष्क्रिय ही रही। वर्तमान में यही, चीन–पाक आर्थिक गलियारा, भारत के लिए एक बड़ी मुसीबात बन गया है।

चीन–पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका पर चुप्पी

साल 1992 में, कांग्रेस सरकार के विदेश राज्य मंत्री आरएल भाटी ने राज्यसभा में अधिकारिक तौर पर बताया था कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। यह समूचा इलाका पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू–कश्मीर का हिस्सा था। फिर साल 2010 में चीन की साम्यवादी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को 'नॉर्दर्न पाकिस्तान' कहकर संबोधित किया था। इन मुद्दों पर भी कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकारों ने चीन और पाकिस्तान की संदिग्ध भूमिका पर चुप्पी साध ली और मुद्दे को अत्यधिक जटिल बना दिया।

यह तो केवल कुछ उदाहरण हैं, जबकि ऐसी घटनाओं की सूची कहीं अधिक लंबी है, जिनमें तत्कालीन भारत सरकार की नीतियों ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू–कश्मीर पर भारत के दावे को दुर्बल किया। यह स्थिति क्रमिक रूप से बिगड़ती चली गई। वास्तव में, इतिहास में कई ऐसे अवसर मिले थे जब परिस्थितियां भारत के पक्ष में जा सकती थीं, किंतु उन्हें या तो नजरअंदाज़ किया गया या वे निष्क्रियता के कारण हाथ से निकल गए।

(यह लेख देवेश खंडेलवाल ने लिखा है। वह बीते 15 वर्षों से लेखन एवं शोध कार्य से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। उन्होंने MyGov इंडिया में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. साथ ही महाराजा हरि सिंह और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर भी शोध आधारित दो पुस्तकों का लेखन लिया है।)

https://www-tv9hindi-com/india-pakistan-occupied-jammu-kashmir-is-result-of-congress-mistakes-devesh-khandelwal-3419391.html

भारत–मॉरीशस संबंध को मज़बूत करती भोजपुरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मॉरीशस यात्रा ने दो देशों के बीच केवल भौगोलिक दूरी को नहीं, बल्कि दिलों को भी जोड़ा है। 11 मार्च 2025 से शुरू हुई यह दो दिवसीय यात्रा कूटनीति के पार जाकर एक भावनात्मक और सांस्कृतिक सेतु बन गई। यह कहानी है भारतीय संस्कृति की, भोजपुरी की मिठास की, और उस भारतीय मूल के समुदाय की, जिसने सदियों बाद भी अपनी जड़ों को सींच कर रखा है।

12 मार्च 2025 को, मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि बने। इस अवसर पर भारतीय सेना की टुकड़ी ने मार्च किया, नौसेना का जहाज पोर्ट लुइस में लंगर डाले रहा, और वायुसेना के स्काईडाइवरों ने आसमान में तिरंगा लहराया। यह महज शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि मित्रता और आपसी विश्वास का प्रतीक था।

मॉरीशस की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा भारतीय मूल का है। इनकी जड़ें 19वीं सदी के उन प्रवासियों से जुड़ी हैं जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने "गिरमिटिया मजदूर" के रूप में गन्ने के खेतों में काम करने भेजा था। अधिकांश उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे, साथ लाए थे अपनी भाषा, अपने गीत, अपनी पूजा–पद्धति और अपनी रसोई के स्वाद। यह प्रवासी कठिन परिश्रम करते थे, पर अपनी पहचान, रीति–रिवाज और बोली को कभी नहीं छोड़ा। भोजपुरी इस विरासत की आत्मा बनी रही.

मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत एक अद्वितीय उत्सव जैसा था। प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ 200 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों, स्थानीय मंत्रियों, और सामुदायिक प्रतिनिधियों ने उनका अभिनंदन

मॉरीशस ने अपनी विरासत को न सिर्फ संजोया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संचारित भी किया है। सवाल अब यह है – क्या भारत भी अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को उतने ही गर्व और संवेदनशीलता से सहेज पाएगा?

–सत्येंद्र त्रिपाठी

किया। लेकिन स्वागत का सबसे जीवंत क्षण तब आया, जब पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत "गीत गवनई" की धुनें पूरे माहौल में गूंज उठीं। इस संगीत ने न केवल कानों को, बल्कि दिलों को भी छू लिया – जैसे इतिहास अपने आप वर्तमान में उतर आया हो।

आज मॉरीशस में भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। यहां के त्योहारों में, विवाह–समारोहों में, और पारिवारिक आयोजनों में इसकी गूंज सुनाई देती है। 2016 में यूनेस्को ने "गीत गवनई" को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया, जिससे इस परंपरा को वैश्विक मान्यता मिली।

"गीत गवनई" कोई साधारण गीत नहीं – यह लोककथाओं, आशीर्वादों और भावनाओं का संगम है। इसे प्रायः महिलाएं गाती हैं, खासकर शादी–ब्याह में, जब दुल्हन को विदा करते समय भावनाओं का ज्वार उमड़ता है। गीतों में गांव की याद, खेतों की महक, और पुरखों की पुकार छिपी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस धुन को सुनते हुए कहा, "यह देखकर गर्व होता है कि भोजपुरी यहाँ भी उतनी ही जीवंत है जितनी हमारे गांवों में।"

आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर, मॉरीशस की गलियों में "भारत माता की जय" और "मोदी–मोदी" के नारे गूंजे। होटल के बाहर भारतीय मूल के लोग तिरंगे लेकर इकट्ठा हुए। यह दृश्य केवल एक नेता का स्वागत नहीं था – यह उस मातृभूमि का सम्मान था, जिससे उनका रक्त संबंध जुड़ा है। मोदी ने भी इसे "खून का रिश्ता" कहा।

यह सांस्कृतिक बंधन केवल भाषाई नहीं है–मॉरीशस के मंदिरों में आज भी सावन के गीत गूंजते हैं, दिवाली पर घरों में दीये जलते हैं, और होली पर रंगों की बौछार होती है।

भारत और मॉरीशस के बीच समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, और व्यापार में गहरा सहयोग है। हिंद महासागर में भारत की "सागर" नीति में मॉरीशस को अहम स्थान प्राप्त है। दोनों देश मिलकर समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, और समुद्री आपदा प्रबंधन जैसी चुनौतियों से निपटते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर, मॉरीशस भारत का एक प्रमुख निवेशक है। पिछले 20 वर्षों में मॉरीशस से भारत में 161 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह द्विपक्षीय कर संधि और निवेश अनुकूल माहौल का परिणाम है। पर्यटन, आईटी, शिक्षा, और नवीकरणीय ऊर्जा में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है।

दोनों देश आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं। हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए मॉरीशस भारत का प्राकृतिक साझेदार है।

निष्कर्ष

मॉरीशस में भोजपुरी की स्थिति भारत के लिए एक आईना है। जहां भारत में इसे अक्सर क्षेत्रीय भाषा कहकर सीमित मान्यता दी जाती है, वहीं मॉरीशस में यह सम्मान और गर्व का विषय है। यह तथ्य हमें अपनी भाषाई विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। भोजपुरी में साहित्य, कविता, रंगमंच और सिनेमा की एक समृद्ध परंपरा है, जिसे और सहेजने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक मिशन नहीं थी – यह सांस्कृतिक पुनर्मिलन का उत्सव थी। यह दिखाती है कि संस्कृति सीमाओं से परे जाती है, और जड़ें चाहे कितनी भी दूर क्यों न हों, वे दिलों को जोड़ती रहती हैं।

मॉरीशस ने अपनी विरासत को न सिर्फ संजोया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संचारित भी किया है। सवाल अब यह है – क्या भारत भी अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को उतने ही गर्व और संवेदनशीलता से सहेज पाएगा? ❑❑

(लेखक लोकनीति संस्थान, लखनऊ के निदेशक हैं।)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

मातृभूमि के विभाजन की वेदना

अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। अखण्ड भारत महज सपना नहीं, श्रद्धा, तपस्या, निष्ठा और जीता–जागता शरीर है। जिन आंखों ने भारत को भूमि से अधिक माता के रूप में देखा हो, जो स्वयं को इसका पुत्र मानता हो। वन्देमातरम् जिनका राष्ट्रघोष और राष्ट्रगान हो, ऐसे असंख्य अंतःकरण मातृभूमि के विभाजन की वेदना को कैसे भूल सकते हैं। अखण्ड भारत के संकल्प का कैसे त्याग सकते हैं? किन्तु लक्ष्य के शिखर पर पहुंचने के लिए यथार्थ की कंकरीली–पथरीली, कहीं कांटे तो कहीं दलदल, कहीं गहरी खाई तो कहीं रपटीली चढ़ाई से होकर गुजरना ही होगा।

सवाल दर सवाल भारत क्या है? क्या वह भूगोल है? क्या इतिहास है या कोई सांस्कृतिक प्रवाह है? यदि भूगोल है तो वह भूगोल को भारत कब मिला, किसने दिया? भूगोल तो पहले भी था पर तब वह भारत क्यों नहीं था? तब उसका नाम क्या था? भारत की अखंडता का अर्थ क्या है? यदि कोई भौगोलिक मानचित्र है जिसे हम अखंड देखना चाहते हैं तो प्रश्न उठेगा कि उसकी सीमाएं क्या हैं?

क्या हम ब्रिटिश भारत की अखंडता चाहते हैं या सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री हवेनसांग के समय के भारत की, जिसमें आज का अफगानिस्तान और मध्य एशिया का ताशकंद–समरकंद क्षेत्र भी सम्मिलित था? या उसके भी पहले के भारत की, जिसे पुराणों में नवद्वीपवती कहा है, जिसके श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बाली, मलेशिया, फारमूसा और फिलीपीन जैसे अनेक द्वीप अंग थे? भारत नाम की भौगोलिक सीमाओं के संकुचन और विस्तार का रहस्य क्या है? उसका आधार क्या है?

भारत बना कैसे? क्या भारत एक दिन में बन गया या उसके पीछे हजारों साल की इतिहास यात्रा विद्यमान है? प्राचीन साहित्यिक स्रोत बताते हैं कि कभी इस भौगोलिक खण्ड को केवल हिमवर्ष कहते थे, फिर उसे "पृथिवी" "अजनाम वर्ष" और "जम्बूद्वीप" जैसे नाम मिले। मौर्य सम्राट अशोक को सकल जम्बूद्वीप का राजा कहा गया। आगे चलकर हमारे संकल्प–मंत्र में " जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते कुरुक्षेत्रे..." जैसे भौगोलिक नामों को गिनाया गया। आलोकित गाथा राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है।

वीभत्स, भारत का विभाजन देश के लिए किसी विभीषिका से कम नहीं थी। यह अंग्रेजों की साजिश थी कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, इसके लिए कुछ भारतीय नेता भी जिम्मेदार थे। विभाजन को याद किया जाए तो 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए इतिहास का एक गहरा जख्म है। वह जख्म तो आज तक ताजा है और भरा नहीं है। यह वो तारीख है, जब 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी।

वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। बंटवारे की शर्त पर ही भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर–बार छूटा, परिवार छूटा। लाखों की जानें गईं। यह दर्द था, विभाजन का। इस बंटवारे से बंगाल भी प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा भारत का रह गया और बाकी पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। दंशभरी विभाजन विभीषिका आज भी नासूर है। संचेतना अखंड और वैभवशाली राष्ट्र का संयोजन ही उपचार है।

(हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार)

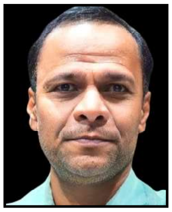

भारत बना कैसे? क्या भारत एक दिन में बन गया या उसके पीछे हजारों साल की इतिहास यात्रा विद्यमान है?

–हेमेन्द्र क्षीरसागर

ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच ने दिया 'विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो' का नारा

अमेरिकी टैरिफ के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच ने 'विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो' का नारा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय समानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच मैदान में कूद गया है।

स्वदेशी जागरण मंच ने समूचे देश में 'विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो' का नारा देते हुए पूरे देश में स्वदेशी सुरक्षा स्वालंबन अभियान शुरू किया है।

बता दें कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर संघ समर्थित संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने मुहिम शुरू करते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में 10 अगस्त को शाम पांच बजे से सांकेतिक धरना–प्रदर्शन (प्रोटेस्ट) का आयोजन किया।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने देशवासियों से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों से सामान नहीं खरीदने की अपील की है। उन्होंने लोगों से देश में निर्मित स्वदेशी अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सभी भारतीय अपने भारतीय प्लेटफॉर्म पर ई–कॉमर्स करें।

उन्होंने यह भी बताया कि स्वदेशी जागरण मंच अब अमेजन, कोकाकोला, पेप्सी, केएफसी सरीखी अमेरिकी कम्पनियों और प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की मुहिम छेड़ेगा। बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया जाने वाला सबसे ज्यादा टैरिफ है। अमरीकी सरकार द्वारा मनमाने तरीके से भारत पर थोपा गया टैरिफ 30 अगस्त से प्रभावी हो चुका है।

https://www-abplive-com/news/india/us-tariffs-on-india-swadeshi-jagran-manch-gave-slogan-foreign-companies-should-leave-india-campaign-will-be-run-across-country-ann-2993006

स्वदेशी जागरण मंच ने नगर में निकाली संकल्प यात्रा

स्वदेशी जागरण मंच के तत्त्वावधान में प्रान्त प्रचार प्रमुख के नेतृत्व में पूर्व नियोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन गत दिवस स्वयंवर गेस्ट हाउस (उरई) में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कालपी बड़ा स्थान मन्दिर के महंत रामकरन दास महामण्डलेश्वर ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि गौतम त्रिपाठी जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा मुख्य वक्ता लाल सिंह चौहान प्रांत प्रचार प्रमुख उपस्थित रहे।

गौतम त्रिपाठी ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल से हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध, आत्मनिर्भर होगी। उन्होंने कहा, सबको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे महंत रामकरण दास ने सनातन धर्म को मजबूत बनाने हेतु जागरूक होने के लिए कहा। वक्ता लाल सिंह चौहान ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से चर्चा शुरू कर 'स्वदेशी की विचारधारा व समृद्ध भारत बनाएं' जैसे विचार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के अंत में स्वदेशी अपनाने हेतु संकल्प दिलाने के बाद संकल्प यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद जिला संयोजक रामबली सिंह ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोसेवा आयोग के सदस्य राजेश सिंह सेंगर, शिक्षाविद अशोक राठौर, पूर्व अध्यक्ष नपा अनिल बहुगुणा, व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, महिला नेत्री बीजेपी रेखा वर्मा, महिला नेत्री बीजेपी पूजा सेंगर भारत विकास परिषद से अजय इटौं दिया, राजेश निगौतिया, गौशाला संचालिका विनीता पांडे, जिला महिला प्रमुख कमला चौहान, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम से मीना दीदी गायत्री परिवार से लक्ष्मण सिंह, संतोष पूर्व नगर अध्यक्ष, बीजेपी अरुण गुप्ता नगर संचालक आरएसएस लाल सिंह, शिक्षक जगत कुशवाह बालवीर सोनी गेस्ट हाउस संचालक संदीप गुप्ता घंटी सैनिक प्रकोष्ठ से राघवेंद्र सिंह, नवाब सिंह जादौन, जिला सहसंयोजक अनूप मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र विक्रम सिंह महेश कुमार सोनी, डीवीसी प्रो. डॉ. मनोज गुप्ता, इतिहास विद, डॉ. हरिमोहन पुरवार, राम सेंगर, छात्र प्रमुख धर्मेंद्र सेंगर, बृजेश सिंह, सोमेंद्र कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा समेत दो सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रामकुमार जादौन व अखिलेश नायक ने किया।

गोरखपुर में गूंजा स्वदेशी बिगुल, अमरीकी टैरिफ का विरोध

स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो अभियान के अंतर्गत आयोजित शंखनाद रैली एवं स्वदेशी संकल्प यात्रा का आज गोरखपुर में समापन हुआ। नगर के इंदिरा तिराहा, गोलघर से प्रारंभ होकर यात्रा टाउन हाल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर संकल्प सभा के साथ समाप्त हुई। यात्रा में व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर, तख्तियां और गगनभेदी नारों के साथ विदेशी कंपनियों, अमेरिकी टैरिफ और आर्थिक तानाशाही के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया।

स्वदेशी जागरण मंच, गोरक्षप्रांत प्रांत संयोजक धीरज राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ भारत की आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला है। यह हमारे उद्योग, व्यापार, किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों को कमजोर करने की साजिश है। भारत अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और श्रमिकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हमें इस आर्थिक गुलामी को तोड़ना ही होगा।

संयुक्त व्यापार मंडल गोरखपुर के संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि विदेशी कंपनियों का मकसद सिर्फ भारतीय बाजार पर कब्जा जमाना है। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मणिनाथ गुप्ता ने कहा कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई–कामर्स दिग्गज छोटे व्यापारियों के हत्यारे हैं। दवा विक्रेता समिति के जिला अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा अमेरिका की आर्थिक तानाशाही और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर हमला हैं। गोलघर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अभिषेक शाही और उपाध्यक्ष गौरी शंकर सरावगी ने कहा स्वदेशी अपनाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय कर्तव्य है। डिस्ट्रीब्यूटर एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने कहा हर भारतीय को अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिला संयोजक राजेश गुप्ता ने कहा कि यह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की दूसरी क्रांति है।

भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक भोला अग्रहरि, गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के महामंत्री विशाल गुप्ता, असुरन व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, अशोक गुप्ता, अशोक गुप्ता, गौरव गुप्ता, दिलीप गुप्ता, भानु प्रताप चंद, हरिश्चंद्र, राजेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अनिमेष सिंह, राकेश पांडे, धर्मेंद्र चंद, विश्वंभर राय, अभिषेक राय, हेमंत तिवारी, राम हंस मौर्य, विपिन पांडे, राहुल उपाध्याय, संजय शुक्ला, डा. अजय तिवारी, अमरेश मिश्रा, अमरेंद्र तिवारी, बहादुर उपाध्याय, आदित्य गुप्ता, विधयवासिनी अग्रहरि, दिनेश जायसवाल, संजय शिलांकुर सहित अनेक व्यापारी नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्वदेशी का संकल्प घर–घर पहुंचायें : महेश पोद्दार

अगस्त क्रांति के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में सरला बिरला विश्वविद्यालय के सभागार में 'स्वदेशी शंखनाद' का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर वर्तमान परिवेश में स्वदेशी घर–घर तक पहुंचे इसके लिए स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के पत्रिका का लोकार्पण भी हुआ। इसका उद्देश्य स्वदेशी संकल्प को घर–घर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा होने पर इस देश को स्वावलंबी बनाना है। इसी की शिक्षा देश के प्रधानमंत्री ने हम सभी को दी है। उन्होंने स्वदेशी के लिए संकल्प करने तथा घर–घर जाकर सूची बनाने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि भाजपा झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर ने कहा कि हमें अपने उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाकर स्वदेशी सामग्री की खरीदारी करनी होगी। स्वदेशी सामग्रियों का इस्तेमाल

करेंगे तो इसका फायदा देश को ही होगा।

इस कार्यक्रम की भूमिका और प्रस्तावना रखते हुए स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय कुमार ने कहा कि हमें छोटा सा ध्यान करना है कि जब भी हम दुकान पर जाएं दुकानदार भैया से पूछे कि जो सामान दे रहे हैं यह विदेशी सामग्री तो नहीं है। उसके बाद ही सामग्री की खरीदारी करें। सरला बिरला विश्वविद्यालय के महानिदेशक गोपाल पाठक ने कहा कि हमें ब्रांडेड सामान खरीदने की स्वतंत्रता तो है पर हमें अपने आचरण को भी ब्रांडेड बनाने की आवश्यकता है।

मौके पर विश्वविद्यालय के सभी छात्र– छात्राओं को हस्तकला से बनी हुई प्रभु श्रीराम मंदिर प्रदान किया गया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के विजय छापरिया, प्रकाश हेतमसरिया, सत्य प्रकाश पांडे, सरला बिरला विश्वविद्यालय के पूर्व सचिव सह डीन विजय कुमार सिंह, कुल सचिव श्रीधर, अंचल तिवारी, आलोक प्रमार, राधिका सिंह, देवंती कुमारी, ब्रजेश कुमार, हिमांशु, आशुतोष द्विवेदी, प्रशांत कुमार, प्रवीण कुमार, रविंद तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद थे ।

स्वदेशी जागरण मंच ने ट्रंप का फूंका पुतला, नारेबाजी की

स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत कमला नगर में डोनाल्ड ट्रंप व विदेशी वस्तुओं का पुतला दहन किया। अमेरिकी उत्पाद कोका–कोला को नाली में बहाया।

'जय स्वदेशी – जय जय स्वदेशी' के नारे लगाए और पेप्सी कोला, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट को विरोध जताया। जयघोष में क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच के इस अभियान का समर्थन देने के साथ ही संकल्प लिया कि विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। इस दौरान प्रांत सह समन्वयक उपेंद्र त्रिपाठी, प्रांत सह संयोजक केशव बाजपेई, सिद्धार्थ अग्रवाल, श्याम, शिवम, दीपक, नरेश, अतुल, हरि, अमित आदि मौजूद रहे।

स्वदेशी जागरण मंच ने किया विदेशी कंपनियों का पुतला दहन

स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी कंपनियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मंच की ओर से विरोध में चौघानपाटा में प्रदर्शन कर विदेशी कंपनियों का पुतला फूंका। स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के नारे के साथ लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने का संदेश दिया।

गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मंच के प्रांत सह संयोजक सज्जन लाल टम्टा ने कहा कि विदेशी कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व से देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के छोटे व्यापारियों, कारीगरों और किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं। रोजगार के अवसर घट रहे हैं और स्थानीय उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर ही हम अपने देश की आर्थिक स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच लंबे समय से देशभर में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन अभियान चला रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे दैनिक जीवन में विदेशी वस्तुओं के बजाय देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें।

वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से न केवल स्थानीय उद्योग को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार सृजन में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटाने के लिए ठोस नीतियां बनाई जाएं और छोटे कुटीर उद्योगों को सशक्त किया जाए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान, विनीत बिष्ट, कैलाश गुरुरानी, बीना नयाल, अर्जुन बिष्ट, दिनेश मठपाल, कमला तिवारी, कविता वर्मा, मनीष जोशी, रेखा तिवारी, पूनम पालीवाल, गोधन भैसोड़ा, आनंद भोज, कृष्ण सिंह, चंदन लाल टम्टा, विनोद गिरि, रोहित भोज आदि मौजूद रहे।

'विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो' अभियान के तहत छात्राओं ने निकाली रैली

स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान संचालन समिति के तत्वावधान में अगस्त क्रान्ति दिवस के अवसर पर विदेशी कम्पनियों भारत छोड़ो अभियान के अनतर्गत आर्य महिला इण्टर कालेज एवं आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय कि छात्राओं ने नगर के विभिन्न मार्गों पर रेली निकाल कर अमेरिका के टैरिफ वृद्धि के विरोद्ध में प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर छात्रायें विभिन्न प्रकार के नारे लगा रही थी जैसे– 'कर्तव्य निभाए स्वदशी अपनाए', अगस्त क्रान्ति दिवस वीरो की मिसाल स्वदेशी का कमाल, स्वदेशी ही शक्ति है, भारत राष्ट्र की भक्ति है, स्वदेशी हमारी स्वाभिमान है, यही भारत की पहचान है। 'जन–जन की यही पुकार स्वदेशी से चमके भारत हर बार', 'स्वदेशी अपनाओं भारत को आगे लाओ'। 'जन जन की यही पुकार राष्ट्र रक्षा में हो स्वदेशी पहला आधार'।

स्वदेशी जागरण मंच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संयोजक डा. अमितेश अमित ने अपने सम्बोधन में कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का आंदोलन नहीं था, बल्कि आर्थिक सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और सभ्यतागत संप्रभुता का दावा भी था। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन, वास्तव में विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार करने, घरेलू उत्पादन को बहाल करने और भारत में आत्मनिर्भर आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण का एक आह्वान था। कार्यक्रम में डा. सारिका अग्रवाल, डा. श्वेता सक्सेना, डा. आशीष गोयल, डा. एम. पी. एस. चैहान, डा. गुलशन रस्तोगी, कु. शेशांकी, अनीता वाजपेई, शिखा रानी, पूर्णिमा श्रीवास्तव, मनीष मिश्रा, हिमान्शु सोनवानी राकेश वर्मा एवं बड़ी संख्या में आर्य महिला डिग्री कालेज एवं आर्य महिला इण्टर कालेज की छात्रायें उपस्थित रहीं।

स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ अभियान चला

स्वदेशी जागरण मंच ने बागेश्वर नगर में स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत रैली निकाली। नुमाईशखेत मैदान पर बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी, छात्र, महिलाएं तथा सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र हुए। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां तथा बैनर थामे स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ और देशी अपनाएं, देश बचाएं जैसे नारे लगाए।

रैली नुमाईखेत मैदान से निकलकर एसबीआइ तिराहे तक पहुंची। यहां विदेशी उत्पादों का पुतला फूंका। लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। सह प्रांत संयोजक सज्जन लाल टम्टा ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों तथा उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रानिक्स और रोज़मर्रा की जरूरतों की चीज़ों में भी स्वदेशी उत्पाद को प्राथमिकता दें।

रैली के समापन पर मंच के पदाधिकारियों ने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वह आने वाले त्योहारों में और दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर राष्ट्रहित में योगदान देंगे। इस मौके पर नंद किशोर पंत, हेमंत कुमार टम्टा, दामोदर जोशी, प्रमोद मेहता, विवेक तिवारी, तारा सिंह रावत, एसएस तोपाल, कमलकांत पांडे, प्रमोद कुमार, सुनीता टम्टा, भावना रावत, तारा शकर पाठक, सागर सिंह भैसोड़ा आदि उपस्थित थे। ❑❑

स्वदेशी बैठकें

सचित्र झलक

स्वदेशी शंखनाद, रांची

विचार वर्ग, असम (उत्तर)

पंचकूला, हरियाणा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 अगस्त 2025
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी संकल्प यात्रा

सचित्र झलक

अगरतला, त्रिपुरा

इटा, उ.प्र.

उत्तराखण्ड

बागपत, उ.प्र.

इम्फाल, मणिपुर

भदोही, उ.प्र.

हरदोई, उ.प्र.

इटावा, उ.प्र.

कानपुर

झालावाड़, राज.

झांसी

कालाहांडी, उड़ीसा

लखनऊ

मैनपुरी

मंडी, हि.प्र.

मणिपुर

मुरादाबाद

नीलगिरि, तमिलनाडु

प्रयागराज

शाजापुर, म.प्र.

शाहजहांपुर, उ.प्र.

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती